

जनता का राज्य

मनमोहन चौधरी



केन्द्राय गांधी स्मारक निधि
नई दिल्ली

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि
राजघाट, नई दिल्ली
के लिए
मन्त्री, सर्व सेवा सघ, वाराणसी
द्वारा प्रकाशित

प्रतियाँ : ३,०००
दिसम्बर, १९६६
मूल्य : २७ पैसे

भूमिका

गांधी-जन्म-शताब्दी के निमित्त यह छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

सभी जानते हैं कि विनोबाजी भूदान-ग्रामदान-आन्दोलन के प्रवर्तक हैं। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोदय-विचार को मूर्त रूप देना इस आन्दोलन का उद्देश्य है।

इस पुस्तिका के लेखक श्री मनमोहन चौधरी आज त्रिविध कार्यक्रम के नाम से ग्रामदान, छादी और शान्ति-सेना का जो आन्दोलन चल रहा है, उसके प्रमुख नेताओं में से एक हैं।

भारत की नवरचना में सचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए कि त्रिविध कार्यक्रम के मूल तत्त्व क्या हैं और ग्रामदान में भाग लेनेवाले लाखों ग्रामीणों पर आज उसका क्या परिणाम हो रहा है। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में न केवल भ्रष्टा रखता है, बल्कि सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते देशभर में इसे कार्यान्वित करने में तत्परता से लगा है, उस व्यक्ति से बढ़कर कौन होगा, जो इस विषय को ठीक से प्रस्तुत कर सके।

आशा है, पाठक इस पुस्तिका में वर्णित उन परिणामों पर खास ध्यान देंगे, जो न केवल उस गहन विचार पर, बल्कि ग्रामीण भारत के साथ

सीधा सम्पर्क रखनेवाले उन हजारों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भी प्रकाश डालते हैं ।

पुस्तिका सरल और सुबोध शैली में लिखी गयी है तथा अनुभवों से भरी है । मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका प्रत्येक पाठक के लिए बोधप्रद सिद्ध होगी और ग्रामीण बन्धुओं की समस्याओं का और उनके समाधान का उन्हें परिचय करा सकेगी ।

—रं० रा० दिवाकर

अध्यक्ष

गांधी स्मारक निधि

त्रिमूर्ति की उपासना

हमें त्रिविध कार्यक्रम चलाने हैं : एक कार्यक्रम है, सुलभ ग्रामदान का, दूसरा है, ग्रामाभिमुख खादी का और तीसरा है, शान्ति-सेना का । ये तीनों मिलकर एक कार्यक्रम है ।

इनमें से जहाँ एक चीज है, वहाँ बाकी दो चीजें लानी हैं; जहाँ दो चीजें हैं, वहाँ तीसरी चीज लानी है; और जहाँ तीनों नहीं हैं, वहाँ तीनों लानी हैं ।

लोगों के सामने चिन्तन के लिए कार्यक्रम त्रिविध रूप में रखा गया है । हरएक को खास चिन्तनिका होती है, इसलिए हरएक कार्यक्रम के बारे में अलग-अलग सोचना पड़ता है; लेकिन हमको अलग-अलग काम नहीं करना है । हमें तीनों को एकत्र करके काम करना है । त्रिमूर्ति की उपासना करनी है । त्रिमूर्ति में तीन अलग-अलग मूर्तियाँ नहीं हैं, एक ही है ।

हमने जब जीवन-दान दिया था, तो उसके साथ हमने मंत्र दिया था । वह मंत्रपूर्वक दान था । उसमें कहा गया था : “भूदानमूलक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रान्ति के लिए मेरा जीवन-दान ।” आज जो सुलभ ग्रामदान है, वह भूदान का विकास है; जो ग्रामाभिमुख खादी है, वह ग्रामोद्योग का सर्वोत्तम प्रतीक है; और शान्ति-सेना के द्वारा अहिंसक क्रान्ति आ सकती है ।

इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह संकट-मोचन का कार्यक्रम है—भारत के ही नहीं, विश्व के भी संकट-मोचन का । क्योंकि इससे लोक-शक्ति खड़ी होती है । यदि हम लोक-शक्ति खड़ी नहीं करेंगे, यदि गाँव के गरीब लोगों की जिम्मेदारी गाँववाले नहीं उठावेंगे और राज्य-शासन की अपेक्षा करते रहेंगे, तो स्वतन्त्रता का मूल्य, लोकतन्त्र का मूल्य और समाजवाद का मूल्य—तीनों मूल्य टिक नहीं पायेंगे । और फिर तो भारत ही सारे विश्व को आग लगाने का साधन सिद्ध हो सकता है ।

—विनोबा

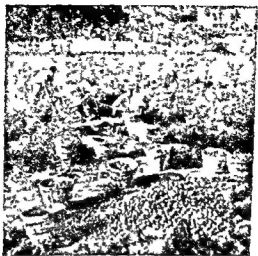
अनुक्रम

१. स्वतन्त्रता के बाद	१
२. ग्रामदान	५
३. ग्रामदान, सरकार और योजना	१३
४. ग्रामदान : प्रतिरक्षा-साधन	१९
५. कुछ समस्याएँ	२२
६. ग्रामदान-आन्दोलन की स्थिति	२७
७. खादी	३३
८. खादी का व्यापक महत्त्व	४०
९. शान्ति-सेना का आदर्श	४५
१०. शान्ति-सेना का कार्य	५०
११. उपसंहार	६०



विनोबाजी पदयात्रा करते हुए





शामदान के बाद पैदावार की बहार



कलबे से भूमिहीन आज के किसान

स्वतन्त्रता के वाद

"आजाद हिन्दुस्तान में नयी दिल्ली के विशाल भवनों और उनके बगल में बसी हुई गरीब मजदूर-वस्तिनों के टूटे-फूटे शीपड़ों के बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है, वह एक दिन को भी नहीं टिकेगा।"

गांधीजी ने ये वाक्य स्वराज्य मिलने के कई वर्ष पहले कहे थे। लेकिन अभी तक यह विषमता बनी हुई है, यही नहीं, बल्कि दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्त हुए २० वर्ष हो रहे हैं, फिर भी देश की अधिकांश जनता गरीबी में डूबी हुई है। भूख और बेकारी बाधक है। लाखों लोग आज भी अज्ञान और रोग के शिकार हैं।

आजादी के पहले अनेक सत्रों में भी लोग उठ खड़े हुए और आजादी के लिए लड़े—उनके मन में यह आशा थी कि स्वराज्य मिलते ही ये सारे दुःख दूर हो जाएंगे।

यह आशा बेमसलब नहीं थी। आज हम एक ऐसे असाधारण युग में जी रहे हैं, जिसमें ज्ञान की सीमा बहुत बढ़ गयी है। विज्ञान ने हमारे हाथ में बड़ी अद्भुत शक्ति दे दी है। धारों और आधुनिक विज्ञान के समतुल्य दिखाई दे रहे हैं। यदि इस शक्ति का सही लाभ उठाया जा सके, तो धरती पर स्वर्ग स्थापित हो सकता है। भूख, बेकारी और बीमारी हमेशा के लिए मिट सकती है। सप्ताहभर के लोग सुखी और सतोषमय जीवन बिता सकते हैं।

लेकिन यदि आज की तरह उमरा दुरुपयोग ही होता रहा, और युद्ध और शोषण में ही उमरी मदन सी जाती रही, तो हमारे मारा समाप्त नष्ट

हो सकता है। और इसके लिए वह भयानक शक्ति अणुबम और हाइड्रोजन बम में इकट्ठी की जा रही है।

गांधीजी जानते थे कि हिंसा और विज्ञान का मेल होता है तो वह निश्चित ही विश्व-संहार का कारण बनेगा। अगर अहिंसा के साथ विज्ञान का मेल होता है तो मानवता को शान्ति, मुक्ति और सुख प्राप्त हो सकते हैं।

इसलिए भारत की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने सत्याग्रह जैसा अपूर्व साधन अपनाया और अहिंसक समाज की नींव डालने के लिए अठारह रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इसीको उन्होंने 'सर्वोदय' कहा।

भारत के सामने आज अनेक बुनियादी समस्याएँ हैं। कुछ तो बीते समय के परिणामस्वरूप हैं। विदेशी राज के समय कई समस्याएँ पैदा की गयी थी और बाकी स्वायं और शोषण के लिए विज्ञान का दुरुपयोग करने के कारण पैदा हुई है।

भारत के पास एक भव्य सांस्कृतिक विरासत है। वह एक ऐसा विशाल सागर है, जिसमें असंख्य छोटे-बड़े प्रवाह आ मिलते हैं। उनके मधुर समन्वय से बहुत बड़ी शक्ति और समृद्धि पैदा हो सकती है, परन्तु वह समन्वय अभी हो नहीं पाया है। इसीलिए आज भी हमको भाषा, जाति, धर्म, वर्ग आदि भेदों की सकीर्णता और सघर्ष के दुःखद परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

सैकड़ों वर्षों से बिगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के कारण यहाँ के लोगो में आत्मविश्वास और अभिन्नता की शक्ति नष्ट हो गयी थी। ऐसा विदेशी हुकूमत के कारण हुआ था। गांधीजी ने इस कमी को दूर करने की कोशिश की और काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। फिर भी रोग अभी तक बना हुआ है। यही कारण है कि लोग हमेशा सरकार या किसी महापुरुष की राह देखते रहते हैं कि वे आकर हमारा सारा काम कर देंगे।

आधुनिक उद्योग और व्यापार-व्यवस्था के कारण मुट्ठीभर लोगो के पास सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है। सरकारी मिलकियत के अलावा जितनी भी औद्योगिक और व्यावसायिक सम्पत्ति है, उसके ४६ प्रतिशत की मालिकी केवल ७५ परिवारों के बन्ने में है।

जमीन की मालिकी में भी असमानता है। एक ओर लगभग २० प्रतिशत खेतिहर मजदूर ऐसे हैं, जिनका जमीन पर कोई हक नहीं है, और दूसरी ओर ८० प्रतिशत कृषि-योग्य भूमि अत्यल्प प्रतिशत परिवारों के नियन्त्रण में है।

पहले छोटे-छोटे उद्योग गाँव-गाँव में चलते थे। उनसे करोड़ों लोगो को रोजी मिलती थी। नये उद्योगों ने उन सब छोटे उद्योगों को खतम कर दिया। उनके बदले में दूसरा कोई धधा या रोजगार जुटाया नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि लोग आलसी और काहिली का जीवन जीने को मजबूर हुए।

ये चन्द बुनियादी सवाल हैं, जो आज हमारे सामने हैं। अनाज की कमी, महँगाई, बेकारी, शोषण वगैरह अनेक समस्याएँ हैं, जो परेशान कर रही हैं। उन सबका हल तब तक सम्भव नहीं है, जब तक हम सबसे पहले किसानों का प्रश्न हाथ में न लें। सरकार की ओर से जितने भी प्रयत्न हुए, सबके सब असफल हुए, जनता पर उनका जरा भी परिणाम नहीं दिखाई देता। इन सब समस्याओं को हल करना शायद सरकार के बस की बात नहीं है। यही बात गांधीजी कहते थे और आज विनोबा भी कह रहे हैं।

सरकारों की शक्ति की तुलना में लोक-शक्ति की ताकत बहुत बड़ी है। जनता ही सरकार बनाती है या तोड़ती है, और शान्ति करके बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिखाती है।

आज तक जितनी भी शान्तियाँ हुई हैं, उनमें अधिकतर शान्तियाँ हिंसक रही हैं। गांधीजी ने अपने सत्याग्रह-आन्दोलनों से यह दिखा दिया कि शान्ति अहिंसक भी होनी है। उन्होंने देश को आजाद होने में मदद की। वे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी शान्तिमय उपायों से करने में मदद करना चाहते थे, शान्तिमय सामाजिक शान्ति करने की उनकी तमन्ना थी। गांधीजी ने बाद उस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न विनोबाजी कर रहे हैं। स्वराज मिलने के बाद आज के नये सदर्भ में विनोबाजी ने सर्वप्रथम भूमि-समस्या को हाथ में लिया और उसके समाधान के लिए

भूदान-आन्दोलन प्रारम्भ किया । इसीसे आगे चलकर ग्रामदान-आन्दोलन निकला ।

गांधीजी द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में खादी और शान्ति-सेना प्रमुख कार्यक्रम थे । ये तीनों—ग्रामदान, खादी और शान्ति-सेना—मिलकर आज त्रिविध कार्यक्रम कहलाते हैं । गांधीजी के अन्य सब रचनात्मक कार्यक्रम इन्हीं तीन में समाये हुए हैं, क्योंकि जैसे विनोबाजी कहते हैं "मौ को निमंत्रित किया, तो उसके साथ बच्चे मौ आते ही हैं ।" यह 'त्रिविध कार्यक्रम' उन सब कार्यक्रमों के लिए द्वार खोल देता है और अनुकूल वातावरण निर्माण कर देता है ।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय समाज में ऐमा शान्तिमय परिवर्तन लाना है, जो क्रान्ति से किसी कदर कम नहीं है । हमारा विश्वास है कि यही एक कार्यक्रम है, जो लोगों में चारों ओर घिरी हुई समस्याओं का हल करने की शक्ति जगा सकेगा और वह दिन ला सकेगा कि जब 'महल के बगल में झोपड़े न रहें ।'

ग्रामदान

ग्रामदान-आन्दोलन भूदान का ही विकसित रूप है। भूदान अप्रैल १९५१ में आरम्भ हुआ था।

पहले हैदराबाद रियासत थी। उसका एक जिला है तेलंगाना। वह भाग अब आंध्र-प्रदेश में मिल गया है। वहाँ उन दिनों किसानों के बीच भयकर अशान्ति भड़क उठी थी। भारत के दूगरे हिस्सों की तरह वहाँ भी कृषि-योग्य भूमि का ज्यादा हिस्सा मुट्ठीभर लोगों के हाथों में था और मेहनतकश किसानों के हाथ में या तो बहुत कम था या बिलकुल ही नहीं था। बड़े-बड़े जमींदारों से जमीन छीनने का एक हिस्सा आन्दोलन वहाँ छिड़ा हुआ था और भूमिहीन तथा गरीब लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया था। वहाँ शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना भेजी गयी थी और उसके कारण बड़े जोरों की र्यूं-घरायी मची हुई थी।

गरीबों को न्याय दिलाने और शान्ति स्थापित करने का कोई उपाय खोजने के लिए विनोबाजी उस क्षेत्र में गये। वे गाँव-गाँव पैदल जाते थे, लोगों से मिलते थे और परिस्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन करते थे। एक गाँव की सभा में वहाँ के कुछ भूमिहीन किसानों ने उठकर कहा कि हमें यदि थोड़ी-सी जमीन मिल जाय तो हम आराम से गुजारा कर लें। तुरन्त रामचन्द्र रेड्डी नामक एक सज्जन ने उन गरीबों में बाँटने के लिए अपनी सौ एकड़ जमीन दान कर दी और वही से भूदान-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

भूमि-समस्या हमारे देश की सबसे बड़ी और बुनियादी समस्याओं में से एक रही है। भूमि की मांगों में इतनी बड़ी असमानता है कि लगभग

१६ प्रतिशत विस्तार एकदम भूमिहीन है, और इससे कुछ अधिक लोगों के पास बहुत कम भूमि है। बड़े जमींदारों की संख्या अधिक है, लेकिन वे स्वयं खेती नहीं करते। गरीब किसान उनसे बटाई पर या टीके पर जमीन लेते हैं। इससे शोषण, बेदखली और बेहद मालगुजारी आदि अन्यायों को बल मिलता है।

स्वराज्य के बहुत पहले ही कांग्रेस और दूसरे प्रगतिशील राजनैतिक पक्षों ने भूमि-सुधार की आवश्यकता महसूस की थी। स्वराज्य मिलते ही जमींदारी, मालगुजारी आदि बीच की व्यवस्था तो हटा दी गयी, लेकिन भूमि के अधिक समान वितरण का कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया। कई राज्यों में भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा (सीलिंग) का कानून लागू हुआ। चूंकि यह मर्यादा काफी बड़ी थी, इसलिए भूमिहीनों में बांटने के लिए इसमें से बहुत कम जमीन निकल पायी। सीलिंग के कानून के कारण इतना ही हुआ कि बड़े जमींदारों के बीच नये सिरे से भूमि का पुनर्वितरण हुआ। पहले जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ों की मालिकी थी, और अब सीलिंग की सीमा के अन्दर कई टुकड़ों में वही मालिकी बनी रही।

विदेशी तंत्रों ने भी कहा था कि भूमि-सुधार तुरन्त करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट सूचित किया था कि एकमात्र भूमि-सुधार से ही कृषि-उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा जाग सकती है। यदि पर्याप्त मात्रा में अन्नोत्पादन नहीं बढ़ेगा तो पंचवर्षीय योजनाएँ विफल हो जाएँगी। फिर भी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया और आज उसीका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है।

भूदान भूमि-समस्या का हल करने का एक स्वतन्त्र और स्वैच्छिक प्रयास था। विनोबाजी जैसे जैसे तेलगाना से देशभर में पद यात्रा करते गये, वैसे-वैसे यह आन्दोलन सर्वत्र फैलता गया। कुछ ही वर्षों में भूदान के द्वारा लगभग ४० लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई। लेकिन इसमें से लगभग १० लाख एकड़ जमीन ४ लाख परिवारों में बांटी जा सकी है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि सीलिंग का कानून लागू करके जो अतिरिक्त

जमीन प्राप्त की गयी, उससे यह जमीन कुछ ज्यादा ही है । (भू-प्राप्ति और वितरण का चार्ट अन्त में देखिये ।)

भूदान-आन्दोलन के कारण देश में एक नयी आशा और नये उत्साह की लहर दौड़ गयी । उससे ग्रामीण क्षेत्र की अन्यान्य समस्याओं पर भी नयी रोशनी पड़ने लगी । देश में और देहातों में जो पुरानी व्यवस्था चालू थी, वह समाज में फूट और भेद-भाव ही बढ़ानेवाली थी । नये आदर्शों के अनुरूप उसकी पुनर्रचना करने की आवश्यकता थी, ताकि नया प्राण-संचार हो सके । भारत की सभ्यता का, राजनीति का और अर्थ-नीति का मुख्य आधार यहाँ के देहात हैं । भारत को जीवित रहना है तो उन देहातों की सृष्टि को छोड़कर नहीं चल सकता ।

वर्षों पहले से गांधीजी और देश के अन्य विचारक ग्रामों की नवरचना पर जोर देते रहे । अब ग्रामदान-आन्दोलन के कारण ग्रामों में चेतना जाग्रत करने का और ग्रामीण समस्याओं के समाधान की नयी दिशा का मार्ग खुल गया ।

सन् १९५२ की बात है । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में विनोबा-जी की पद-यात्रा चल रही थी । तब मगरौठ गाँव के निवासी उनके पास आये और अपनी सारी भूमि भूदान में दे दी । यही से ग्रामदान-आन्दोलन का जन्म हुआ और मगरौठ को भारत का प्रथम ग्रामदान होने का श्रेय मिला ।

उस घात को अब १४ वर्ष हो गये । यह आन्दोलन देश के सभी भागों में दूर तक फैला और आज देशभर में (ता० ३१ अक्तूबर '६६ तक) २९,०९१ ग्रामदान हो गये हैं । इस बीच ग्रामदान के विचारों में कुछ संशोधन किया गया । मुलभ ग्रामदान के नाम से वही संशोधित रूप आज चल रहा है । हर तरह के लोगों के लिए वह आसान लगता है ।

गाँवों में आमूल परिवर्तन करना ग्रामदान का लक्ष्य है । आज गाँव केवल बहनेभर के गाँव हैं । असल में वह कुछ झोपड़ों के झुण्ड के सिवा कुछ नहीं है । अलग-अलग जातियों, मनीषताओं और प्रत्येक वर्गों के

गाँव को एक ग्रामसभा बनाना ही है। गाँव के सभी बालिग स्त्री पुरुष उसके सदस्य होंगे। ग्रामसभा अपने अध्यक्ष और मंत्री का चुनाव करेगी, और गाँव बड़ा होगा तो एक कार्यकारिणी समिति का भी गठन करेगी। गाँव का सारा व्यवहार ग्रामसभा करेगी, गाँव की आर्थिक प्रगति की योजना ग्रामसभा बनायेगी, लोगों की नैतिक उन्नति का खयाल ग्रामसभा रखेगी, अनाथ, विधवा, बीमार आदि के लिए जरूरी व्यवस्था भी ग्रामसभा ही करेगी। माता की तरह ग्रामसभा गाँव के प्रत्येक व्यक्ति का खयाल रखेगी। वही गाँव की वास्तविक सरकार है। यह सारा कारोबार चलाने के लिए ग्रामसभा की बैठक समय-समय पर हुआ करेगी।

कई राज्या में ग्रामदान-कानून बन गया है। उसमें सौ या उससे अधिक आबादीवाले गाँव की ग्रामसभा को ग्राम-पंचायत के सारे अधिकार देने की व्यवस्था है। इससे पंचायती राज को बहुत बड़ा आधार मिलता है।

समस्त ग्रामीणों की सामूहिक इच्छा का एकमात्र प्रतिनिधित्व ग्राम सभा करेगी। गाँव के बाहर के सभी मामलों में गाँववालों की तरफ से ग्रामसभा ही व्यवहार करेगी। इससे होगा यह कि लोगों को साहूकार, व्यापारी, सरकार, कर्मचारी, पुलिस आदि के साथ अबेले-अबेले उलझना नहीं पड़ेगा। इस तरह से लोग परेशानी और बरबादी से छुटकारा पायेंगे, जिनसे वे आज तबाह हैं।

ग्रामसभा के सारे निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। सर्वसम्मति न हो सकती है, तो सर्वानुमति से या भारी बहुमत से होंगे। क्योंकि भूमि-व्यवस्था, ग्रामकोष का विनियोग आदि बड़े-बड़े मामले में सबका एक-राय होना जरूरी है। इसी तरह से ग्रामसभा को दूसरे-दूसरे नियम और कानून भी बनाने होंगे।

हमारे गाँवों के लिए दलबन्दी एक महान् अभिशाप है। कई गाँवों में दो-दो, तीन-तीन दल बन गये हैं। उनके झगड़े के कारण गाँववालों का जीना दूबर हो गया है। इस दलबन्दी में राजनैतिक पक्षों ने आग में

पुआल का काम किया है । आज के लोकतन्त्र में बहुमत से निर्णय करने की जो पद्धति चालू है, उसने इस दलबन्दी को और प्रोत्साहन दिया है । इस दलबन्दी की जगह गांव को एबता में बांधे रखने का और गांव की शक्ति दिन-ब-दिन बढ़ाने का काम सर्वानुमति से निर्णय करने की पद्धति अपनाने से ही सम्भव होगा । जहाँ-जहाँ भी यह पद्धति अपनायी गयी, वहाँ इसका अच्छा परिणाम देखने में आया है । इसके कारण लोगों में धीरज बढ़ता है और दूसरों के दृष्टिकोण का आदर करने की वृत्ति पैदा होती है ।

ग्रामकोष

प्रत्येक ग्रामदानी गांव को अपना एक ग्रामकोष बनाना होगा । उसमें गांव का प्रत्येक किसान अपनी उपज का ४०वां भाग देगा । जो खेती के बदले दूसरे धंधे करते हैं, उन्हें अपनी आय का ३०वां हिस्सा नकद देना होगा या उतना थम देना होगा । इस हिस्से का प्रमाण घटाने-बढ़ाने का अधिकार ग्रामसभा को होगा । ग्रामकोष का विनियोग ग्रामसभा करेगी । कृषि-मुधार के लिए, ग्रामोद्योगों के लिए और दूसरे-दूसरे विकास-कार्यों के लिए उसका उपयोग हो सकता है । उस कोष से गांव के लोगों को मामूली ध्याज पर कर्ज भी दिया जा सकता है । बूढ़ो, विधवाओं, अशक्त और अनाथ आदि को भी इस कोष से सहायता दी जा सकती है ।

सरकार को अपना काम चलाने के लिए कर आदि के रूप में कुछ आय का जरिया भी खोजना पड़ता है । ग्रामकोष ग्राम-सरकार का खजाना है । लेकिन सरकार में और ग्रामसभा में एक फर्क है । सरकारें दबाव से कर (टैक्स) वसूल करती हैं, परन्तु ग्रामकोष में लोग प्रेम से और स्वेच्छा से अपना हिस्सा देंगे ।

आज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव में मजदूत की वृत्ति है । इसमें हर कोई दूसरे का जरा भी ध्याल न करे हुए अपने लिए घटोरने की कोशिश करता है । नयी व्यवस्था—उसे चाहे समाजवाद

कहें या सर्वोदय—सभी सम्भव है, जब बि लोग आपस में बाँट-बाँटकर जीने लगे। उसके मूल सिद्धान्तों में 'दान' एक प्रमुख तत्त्व रहेगा।

दान सतत जारी रहना चाहिए। प्रत्येक को न केवल एक बार अपनी भूमि का हिस्सा देना है, बल्कि हमेशा कुछ-न-कुछ देते ही रहना है। श्रमिक श्रम देगा, साहूकार धन देगा, शिक्षक और कर्मचारी अपना बौद्धिक श्रम दे सकता है। इस प्रकार ग्रामकोष एक नयी भावना और नयी दृष्टि का प्रतीक होगा।

जब इस प्रकार गाँव के कुल भूमिदानों के ७५ प्रतिशत लोग तथा कुल आबादी के ७५ प्रतिशत लोग उपर्युक्त चारों शर्तों को मान्य करके सकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और गाँव की कुल जमीन के बम-से-कम ५१ प्रतिशत अंश का स्वामित्व ग्रामसभा को सौंप दिया जाता है, तब वह गाँव ग्रामदान घोषित होता है।

इस पर और भी कई कानूनी कार्रवाईयाँ करनी होती हैं। वह सब पूरी होने पर बानूनन् वह ग्रामदान मान्य होगा। यह सब करने-कराने के लिए सभी राज्यों में भूदान-बोर्ड या ग्रामदान-बोर्ड बने हुए हैं। ●

ग्रामदान, सरकार और योजना

स्वराज्य मिलने के बाद देश के व्यवस्थित विकास के लिए अरबों रुपये खर्च किये गये। अनेक बड़े-बड़े और महत्त्वपूर्ण कारखाने खोले गये, बड़े-बड़े बाँध बाँधे गये, हजारों मील लम्बी सड़कें बनायी गयी और रेलवे लाइन बिछायी गयी। असंख्य स्कूल खुले और अस्पताल शुरू हुए। तालाब और कुएँ खोदे गये। पिछले सौ सालों में जितना काम हुआ था, उससे कई गुना अधिक काम इन बीस सालों में हुआ। फिर भी देश की बुनियादी समस्याएँ ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं।

जो भी योजना बनायी गयी, वह सब सतही थी, ऊपर-ऊपर की थी। केवल शहरो को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। यद्यपि देश के ८५ प्रतिशत लोग देहातों में बसे हुए हैं, फिर भी उनकी ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। विनोबाजी अक्सर कहते हैं कि पानी ऊपर से छन-छनकर नीचे जितना आता है, उतना ही नीचेवालों को मिल सकता है। किसी चीज पर पानी ढालें तो वह छनकर नीचे तभी निकलेगा, जब ऊपरी सतह पूरा-पूरा पानी चूस चुनती है। उसी तरह हमारी योजना में भी हुआ यह कि ऊँचे स्तर के लोगों पर ही खूब सारा धन खर्च किया गया। योजना बनानेवालों की आशा थी कि छनकर कुछ तो नीचेवालों को मिल ही जायगा। लेकिन इस तरीके का परिणाम यह हुआ कि धनी अधिक धनी बनते गये, और गरीब जहाँ के तहाँ रह गये। बल्कि और गरीब बन गये।

ऊपरी स्तर के लोगों ने अपने साधारण व्यावहारिक अनुभव के बल पर योजनाओं का पूरा लाभ उठा लिया। जिनके लिए योजना थी, उनका

उस योजना में कोई दखल नहीं था, न योजनाओं को कार्यान्वित करने में उनका हाथ रहा। सब कुछ नीकरशाही के हाथ में था।

हमारे यहाँ अपने ढंग का लोकतन्त्र है। जब तक चलता है, वह अच्छा ही है। लेकिन वह दूर तक जानेवाला नहीं है। पाँच वर्षों में एक बार लोग वोट देते हैं। फिर दूसरे चुनाव तक देश की योजना में और प्रशासन में उनका कोई हाथ नहीं रहता, वे या तो खाली आस लगाये बैठे रहे या बैठे-बैठे झुंझलाते रहे।

ग्रामों की उन्नति के लिए लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किये गये, लेकिन बालू में पानी की तरह सारा धन न जाने कहाँ बिला गया। 'अपना-अपना भला देखो' वाला वही पुराना सिद्धान्त चालू रहा। इसलिए हर कोई इसी ताक में रहने लगा कि सरकारी सहायता का अधिक-से-अधिक लाभ उसे कैसे मिले।

इस स्थिति को सुधारने के प्रयत्न में पचायती राज की स्थापना हुई। लेकिन वह भी अपने उद्देश्य को सिद्ध करने में बहुत सफल नहीं हो सका।

इसलिए विनोबाजी के शब्दों में, यह वैसा ही हुआ, जैसे गाड़ी के आगे घोड़ा बाँधा जाय। जो सत्ता नयी दिल्ली, लखनऊ, बम्बई में केन्द्रित थी, उसके कुछ टुकड़े गाँवों में बाँट दिये गये, उस सत्ता पर गाँव के धनी और साधारण शिक्षित लोगो ने अपना कब्जा जमा लिया। और उसका उपयोग अपने ही कमनसीब भाइयों का शोषण करने में कर लिया। सम्पन्न लोगो के हाथ में गरीबों को कसने का जो शिकजा पहले से ही था, उसकी रहीं-सही कसर इस सत्ता ने पूरी कर दी।

सबसे पहले होना यह चाहिए था कि लोगो की दृष्टि और वातावरण को बदला जाता, ताकि शोषण का शिकजा ढोला पड़ता। तभी पचायती राज से लोगो का कल्याण हो सकता था।

स्वराज्य की बुनियाद में लाखों देशवासियों के त्याग का पुण्य था, इसीलिए उसमें कुछ पवित्रता आयी थी, शक्ति निर्माण हुई थी। पचायती राज भी तभी सच्चा मिट्ट होता, जब कि उसके पीछे त्याग की प्रेरणा होती।

आज उस त्याग और नये दृष्टिकोण का अवसर ग्रामदान से प्राप्त होता है ।

भूमिदान और भूमिहीन आपस में भूमि लेते देते हैं, तो दोनों के बीच सहयोग और मैत्री स्थापित होती है और उससे गाँव में सद्भावनापूर्ण नया और ताजा वातावरण निर्माण होता है । निजी मालिकी खतम होती है । अर्थात् व्यक्ति-व्यक्ति की अपार गरीबी खतम होती है ।

कई राज्यों में ग्राम-पंचायत का आकार बहुत बड़ा है । एक एक पंचायत की जनसंख्या तीन हजार या उससे भी अधिक है । उसके अन्दर १० से २० तक गाँव होते हैं । यह सच्ची ग्राम-पंचायत नहीं हो सकती । किसी भी मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए दस-बीस गाँवों के लोग कभी एकत्र हो नहीं सकते । हाँ, पंचायत के नाम पर हर गाँव के एक-एक या दो-दो प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकते हैं और राज्य-सरकार से प्राप्त सुविधाओं को आपस में बाँट ले सकते हैं । परिणामतः गाँव के बाकी सब लोगों का पंचायत के कामों से न कोई सम्बन्ध आता है, न उसकी उनकी चिन्ता रहती है । ग्राम-पंचायत भी पटना या लखनऊ की विधानसभा की तरह ही जनता से अलग पड़ जाती है ।

सच्ची ग्राम-पंचायत तो एक ही गाँव की बन सकती है, जहाँ के लोग एक साथ बैठ सकते हैं और सब मामलों का प्रबन्ध कर सकते हैं । तभी स्वराज्य का सम्बन्ध सीधे उनके जीवन से जुड़ेगा, उनके नित्य जीवन के आधार पर स्वराज्य खड़ा होगा और उनका अपना स्वराज्य होगा । लोग जब इस प्रकार ग्राम-जीवन के हर मामले में प्रत्यक्ष भाग लेने लगेंगे, तभी लोकतन्त्र वास्तविक होगा, असली होगा ।

ग्रामदानी गाँव की ग्रामसभा से पंचायती राज की ही नहीं, बल्कि स्वराज्य की ही वास्तविक नींव पड़ती है ।

ग्रामदान का मतलब है, ग्राम-स्तर पर गाँव की वास्तविक योजना का प्रारम्भ । ग्रामसभा को गाँव में अनाज की पैदावार बढ़ाने की योजना बनानी होगी, ताकि फल, दूध आदि सभी खाद्य पदार्थों में गाँव स्वावलम्बी

हो। गांव के लोगो को रोजी देने की दृष्टि से छोटे-छोटे ग्रामोद्योग खड़े करने होंगे और वहाँ के कच्चे माल का उपयोग वही करने का प्रबन्ध करना होगा। खरीद-बिक्री का संगठन सहकार-पद्धति से करना होगा। ऐसी तालीम का प्रबन्ध करना होगा कि बच्चे उत्पादनक्षम और उपयोगी नागरिक बन जायें। स्वास्थ्य, सफाई, त्योहार, उत्सव, विवाह और आपसी मतभेद आदि जितने भी प्रसंग हैं, ग्रामसभा को योजना बनाकर अपनी ओर से उन सबकी ठीक-ठीक व्यवस्था करनी होगी। नशा और अन्य व्यसनो पर पाबन्दी लगाने की बात भी सोचनी होगी।

आज गांवों में स्वतन्त्रता नाममात्र की है और उनमें अभिक्रम-शक्ति तो है ही नहीं। सारी शक्ति ऊपर केन्द्रित हो गयी है। ग्रामदान से ग्राम-प्रबन्ध की नींव पड़ती है, जिसमें गांवों को अपने मामले में आरक्षक काम-से-काम रहेगा। सरकार के पास भूमि-सम्बन्धी कागजातो में करोड़ों व्यक्तियों के नाम नहीं रहेंगे, बल्कि गांव का एक ही नाम रहेगा। सरकारी कागजों में सिर्फ गांव के नाम रहेंगे और वही लिखा रहेगा कि उस गांव में इतनी जमीन है, और गांव के नाम पर एक ही पट्टा रहेगा।

इसका प्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि गांव के लोगो को रेवेन्यू विभाग, रजिस्ट्रेशन विभाग और सिविल अदालतों से मुक्ति मिल जायगी। भूमि-सम्बन्धी सारे कागजात ग्रामसभा में रहेंगे। लोगो के बर्जों की जमीन में कोई रद्दोबदल होता है, तो वह वहाँ दर्ज होगा।

जो भी विवाद या झगडा खड़ा होगा, उसे गांव में ही शान्ति से, समाधान-वारक ढंग से निपटाने का प्रयत्न गांववाले खुद करेंगे। गांव से बाहर पुलिस या अदालत की शरण में नहीं जायेंगे। गांव की सम्पत्ति की बरबादी का एक बड़ा जरिया मुचदमेवाजी है। हजारों गांवों में, जहाँ ग्रामदान हो गये हैं, बहुत हद तक मुचदमेवाजी खतम हो गयी है। हर गांव में कई शान्ति-सैनिक और शान्ति-सेवक रहेंगे और वे गांव के अन्दर शान्ति पायाम रखने और अपराध न होने देने का प्रयत्न करेंगे।

गाँव में विभिन्न ग्रामोद्योग खड़े किये जायेंगे । इससे गाँव बड़े-बड़े व्यवसायों के फदे से छूट जायेंगे । इसके बारे में खादी-प्रकरण में विस्तार से चर्चा की गयी है ।

आज लोगों को हर बात के लिए सरकार का मुँह ताकने की आदत पड़ गयी है । वे समझते हैं कि सरकार से जो कुछ मिलता है, सब एकदम मुफ्त दान मिलता है । लेकिन बात ऐसी नहीं है । सरकार जो भी खर्च करती है, उसका पाई-पाई लोगों से करो के रूप में वसूल कर लेती है । खासकर अप्रत्यक्ष कर के रूप में, जैसे कपड़ा, चीनी, माचिस आदि वस्तुओं की एक्साइज ड्यूटी आदि लगाकर । उस धन का बहुत बड़ा भाग उन सरकारी नौकरों पर खर्च होता है, जो ये कर वसूल करने और खर्च करने का काम करते हैं । सरकार हमसे यदि एक रुपया वसूल करती है, तो उसमें से लगभग ४० पैसे तो प्रशासन-व्यवस्था पर ही खर्च कर देती है । खर्च करनेवाले लोग उसमें से बितना हजम कर जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है । ठीकेदार आदि का मुनाफा बगैरह बाद होने के बाद लोगों तक १०० पैसे में से केवल ३० पैसेभर का लाभ पहुँच पाता है ।

इसके विपरीत, यदि ग्रामसभा कर वसूल करती है और खर्च करती है, तो रुपये में कम-से-कम ९० पैसे का लाभ गाँववालों को मिल सकता है । इस तरह से सरकारी काम में होनेवाले भारी अपव्यय को रोकने की शक्ति एकमात्र ग्राम-स्वराज्य में ही है ।

प्रखण्डदान

प्रखण्डदान का नया विचार देश को ग्राम-स्वराज्य की ओर एक कदम आगे ले जानेवाला है । सिंचाई, छोटे उद्योग, माध्यमिक शिक्षा आदि बड़ी विकास-कार्य हैं, जिनके आयोजन की इकाई गाँव से बड़ी होनी चाहिए । प्रखण्ड प्रशासन की भी एक प्रमुख इकाई है । जब प्रखण्ड के सारे गाँव, या लगभग सब गाँव ग्रामदान हो जाते हैं, तो प्रखण्ड-स्तर की पचायत-समिति

अथवा अचल-पचायत ग्राम-स्वराज्य के सिद्धान्तों के अनुसार काम कर सकेगी ।

तब लोगों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर योजनाएँ बनायी जा सकेंगी और वह भी लोग स्वयं बना सकेंगे, फिर उन्हें अमल में लाने के लिए आवश्यक एकता और उत्साह भी ग्रामदानी गाँव के लोगों में पैदा किया जा सकेगा ।

इस समय तक (अक्तूबर '६६ के अन्त तक) ६७ प्रखण्डों का दान हो चुका है और शीघ्र ही सौ प्रखण्ड पूरे हो जायेंगे, ऐसा दीखता है । कई स्थानों पर जिला-दान का विचार भी लोगों के ध्यान में आने लगा है और बिहार के सर्वोदय-कार्यकर्त्ताओं ने पूरे बिहार प्रान्त को ही ग्रामदान में लाने का संकल्प किया है ।

हम इस बात की धल्पना कर सकते हैं, जब कि लाखों गाँव ग्रामदान में आ जायेंगे, तब उसका असर राज्य के प्रशासन पर और राष्ट्र की योजना पर पड़े बिना नहीं रहेगा । इससे दोनों का स्वरूप जड़-मूल से बदल जायगा । उसमें दलित और पीड़ित बहुजन-समाज का हित प्रधान बनेगा । यही ग्रामदान का मुख्य लक्ष्य है । ●

ग्रामदान : प्रतिरक्षा साधन

अक्टूबर १९६२ की बात है। लद्दाख और नेफा क्षेत्र से चीनी सेनाएँ भारत में घुस आयी थी। सारा देश व्याकुल हो उठा था। उस समय विनोबाजी पश्चिम बंगाल में थे। ज्यों ही युद्ध की बात सुनी, फौरन् उन्होंने उद्घोष किया कि भारत की जनता की सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय एकमात्र 'ग्रामदान' है।

बहुतो को यह बड़ा अजीब और नया लगा। लेकिन विनोबाजी के लिए यह नयी बात नहीं थी। इससे पहले भी सन् १९५७ में मैसूर के पास एलवाल में ग्रामदान पर एक राष्ट्रीय परिपद् हुई थी। उसमें विनोबाजी ने इस बात पर जोर दिया था कि ग्रामदान को देशभर में दीर्घ फैलाना चाहिए, जिससे देश में विदेशी आक्रमण को रोकने की शक्ति पैदा हो सके।

उन्होंने कहा था "आज हमारी योजनाएँ यह मानकर बनायी गयी हैं कि दुनिया में शान्ति बनी रहेगी। लेकिन यदि वही कोई विस्फोट हो जाय, या भारत किसी सघर्ष में फँस जाय, तब क्या होगा? हमारा विदेशी व्यापार ठप हो जायगा, उसका प्रभाव आन्तरिक व्यापार-व्यवसाय पर भी पड़ेगा। हमारी सारी योजनाएँ धरी रह जायेंगी। सघर्ष या युद्ध के दिनों में हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ नाकाम साबित होगी।"

सन् १९६५ में भारत का पाकिस्तान से जो सघर्ष हुआ, वह बहुत साधारण था, फिर भी हमारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उससे हमें इस बात की पुरो-पूरी पूर्वसूचना मिल गयी कि यदि बड़ा युद्ध छिड़ता है या विश्व-युद्ध होता है, तो उसका कैसा बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

व्यापार-व्यवस्था टूटती है तो लोगो तक उनकी नित्योपयोगी चीजें पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। इससे दुःख बढ़ेगा, असतोष फैलेगा और लोगो का नीति धर्म और सदाचार कलुषित हो जायगा। यदि गाँव और प्रखण्डो का ग्रामदान हो जाता है, तो सहज ही खाना, कपडा आदि नित्योपयोगी वस्तुओ के बारे में वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, व्यापार और सचार-व्यवस्था के टूटने का असर उन पर बहुत ही कम पड़ेगा।

दूसरी बात यह कि आज देश में शान्ति कायम रखने के लिए बहुत बड़ी सख्या में पुलिस की आवश्यकता है। कई बार तो जब पुलिस की शक्ति कम पड़ती है, तब सेना बुलानी पड़ती है। ग्रामदान हो जाता है, तो गाँव के लोगो में पुलिस और सेना के बगैर ही, खुद अपने क्षेत्र की शान्ति बनाये रखने की सामर्थ्य आती है। इससे पुलिस और फौज की जरूरत नहीं रह जायगी और इनका उपयोग वहीं और हो सकेगा।

वास्तविक सुरक्षा तभी सम्भव है, जब न केवल पूरा राष्ट्र, बल्कि उसका प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक गाँव अन्न के मामले में स्वावलम्बी होगा। यह अत्यावश्यक है। विनोबाजी का आग्रह है कि हर गाँव में हमेशा दो वर्ष के लिए पर्याप्त अन्न का सग्रह रहना ही चाहिए। इससे न केवल गाँव की, बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। यह सब ग्रामदान से ही सम्भव हो सकता है।

आज भारत को चीन से डर है। चीन का भय खाली सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं है। उसकी सम्भावना गाँव-गाँव में है। चीन अपनी सेना के बल पर सारे राष्ट्र को या उसके किसी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। चीनी नेताओ की ऐसी कोई योजना है भी नहीं। वे चाहते हैं कि भारत में साम्यवादी क्रान्ति हो, ताकि क्रान्ति के बाद स्थापित होनेवाली साम्यवादी सरकार चीन के मातहत रह सके।

सीमा प्रदेश में सेना के आक्रमण को रोका जा सकता है, लेकिन विचार के आक्रमण को नहीं रोका जा सकता। "जब तक देश में गरीबी है, भूख है, शोषण है, अन्याय है, तब तक जनता के मन में हिंसक क्रान्ति का आवर्ण

बना रहेगा ।" विनोबाजी की भविष्यवाणी के अनुसार उस परिस्थिति में "गाँव-गाँव में चीन और अमरीका खड़े होंगे ।"

चीन और अमरीका दुनिया को अपनी-अपनी भर्जों के अनुसार आकार देना चाहते हैं और उस आकार-भेद को लेकर ही उन दोनों के बीच आज जानलेवा दुश्मनी है । चीनी नेता सामाजिक और आर्थिक समता लाना चाहते हैं । इस समता के लाने में व्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र मिट जायें, तो उनको उसकी चिंता नहीं है । अमरीका के नेता व्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र पर ज्यादा जोर देते हैं और उसमें आर्थिक समता न भी स्थापित हो और शोषण चालू ही रहे, तो भी वे चिंता नहीं करते । दोनों भारतीयों पर अपना असर डालने का प्रयत्न कर रहे हैं । जिस प्रकार लद्दाख के कई हजार वर्ग किलोमीटर भू-भाग पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, उसी प्रकार अमरीका हमारी अर्थनीति में कुछ महत्वपूर्ण कब्जा जमाये रखना चाहता है ।

मनुष्य के भावी कल्याण की दृष्टि से आर्थिक समता, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, लोकतन्त्र—ये सारे मूल्य बहुत महत्व के हैं । हम इन्हें सर्वथा परस्पर विरोधी नहीं मानते, जैसा आज अमरीका और चीन मानते हैं । यदि अहिंसक साधनों का उपयोग करते हैं, तो तीनों की स्थापना एक साथ हो सकती है । ग्रामदान गाँव का हित-विरोध व्यावहारिक रूप में और सद्भावनापूर्वक मिटा देता है, इसके कारण अमरीका या चीन के बारे में जो भी पूर्वधारणा रही हो, वह सब एक ही झटके से उठ जाती है ।

इस प्रकार ग्रामदान वास्तव में प्रतिरक्षा का एक प्रमुख साधन है । विनोबाजी ने एक जगह कहा था : "हमारा यह दावा नहीं है कि एकमात्र ग्रामदान ही देश को बचानेवाला है । देश की रक्षा के लिए और भी कई चीजें आवश्यक हैं । फिर भी दावे से हम इतना तो कहते ही हैं कि यदि ग्रामदान का आधार न दिया जाय, तो वे दूसरे सारे साधन कुछ भी काम नहीं दे सकेंगे ।"

कुछ समस्याएँ

हमारे गाँवों में तीन प्रकार के लोग रहते हैं १ भू-स्वामी, २ गरीब किसान और मजदूर, और ३ व्यापारी और साहूकार। गाँव के सामूहिक हित की दृष्टि से तीनों प्रकार के लोगों के पास कुछ-न-कुछ उपयोगी सम्पत्ति है। भूमि-स्वामियों के पास भूमि है, मजदूरों के पास धन है, व्यापारी और साहूकारों के पास धन है, व्यवस्था-शक्ति है। ये सभी चीजें गाँव के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए ग्रामदान में इन तीनों को मिलाने का प्रयत्न किया जाता है।

कुछ बड़े जमींदार ग्रामदान में शामिल होने से डरते हैं। वे अपने बच्चों की पढ़ाई, लड़कियाँ के विवाह आदि कई बातों का बन्धन अपने ऊपर महसूस करते हैं और इसीलिए अपनी कीमती जमीन वे छोड़ नहीं पाते हैं। उनका यह भय दूर करने के लिए ही ग्रामदान को 'सुलभ' बनाया गया। इस सुलभ ग्रामदान में उनको गरीबों के लिए अपनी भूमि का अत्यल्प भाग, यानी बीसवाँ हिस्सा देना होता है। ग्रामदान के महान् लक्ष्य की सिद्धि में यह उनका बरणाप्रेरित छोटा-सा त्याग है।

मजदूरों का भय दूसरी तरह का है। कइयों को लगना है कि मजदूरों से कुछ भी काम लेना है तो उनको गरीब और अज्ञानी बने रहना चाहिए और जमींदारों के पैरा के नीचे दबे ही रहना चाहिए। यह धारणा सदियों से चली आयी है। अब जमाने में गुलामी (दास-प्रथा) का रिवाज था। लोग मानते थे कि मजदूरों को पशु की तरह रखें और उनके साथ जानवर के समान व्यवहार करें, तभी वे काम करेंगे। लेकिन अब वे सारे मूढ़ विचार बदल गये हैं। किसी भी सम्पन्न और समृद्ध राष्ट्र में जाकर देखिये, लोग

श्रमिकों से बराबरी का व्यवहार करते हैं। वहाँ के श्रमिकों का रहन-सहन उत्कृष्ट है, वे काफी पढ़े-लिखे होते हैं। आज जो नये-नये मंत्र बने हुए हैं, उनकी तो शिक्षित श्रमिक ही चला सकते हैं, जिनसे व्यापक रूप से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।

इन राष्ट्रो के पूँजीपति भी अब समझने लगे हैं कि श्रमिकों को यदि सुखी और सतुष्ट रखा जाय और उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाय, तो वे ज्यादा उत्पादन करते हैं और अच्छा माल तैयार करते हैं। अब पुराने सारे विचारों को छोड़ने का समय आ गया है।

श्रमिकों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने परिवार के ही सदस्य की तरह समझना चाहिए। गाँव के दूसरे लोगों की तरह ही उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें सुखी और सम्पन्न बनाना चाहिए। इससे गाँव के सब लोगों को नयी वैज्ञानिक पद्धतियों का लाभ मिल सकेगा और उत्पादन कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकेगा। जमींदार अपनी पुरानी धारणाओं से चिपने रहेंगे तो खुद भी कई अच्छी बातों से वंचित रह जायेंगे, जनसाधारण की प्रगति को तो रोकेंगे ही।

व्यापारों और माहूबार भी अवसर ग्रामदान से डरते हैं। माहूबारों को डर है कि बजें में उन्होंने जो धन दिया है, वह वही डूब न जाय। उनको लगता है कि ग्रामदान में जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं रह जाता है, और किसान जमीन बेच नहीं सकेंगे या रहन नहीं रख सकेंगे, नो दावा बर्जा वापस अदा कैसे होगा? लेकिन दरअसल ग्रामदान से उनका पैसा अधिक सुरक्षित होना है। बजें की मारी लेन-देन ग्रामसभा के मार्फत हुआ करेगी। बजें चलाए करने का भार ग्रामसभा पर रहता है। अतएव यह आशानी से समझ में आने जैसी बात है कि व्यक्ति-व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा यह व्यक्ति-साहूबारा के लिए अधिक सुविधाजनक है।

कृषि, व्यापार, या दूकानदारी आदि कोई-न-कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। आज जिनके पास कोई धंधा नहीं है, उन्हें कोई-न-कोई धंधा अपना लेना चाहिए। उधार दें, तो बिना व्याज के देना चाहिए। हाँ, हिसाब-किताब बगैरह या जो कुछ नुबसान बगैरह होता है, उस दृष्टि से मामूली खर्च ले सकते हैं।

व्यापारियों को डर है कि ग्रामदान में उनका मुनाफा छिन जायगा। लेकिन ग्रामदान से तो उत्पादन बढ़ता है, और जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे रुपये-पैसे का व्यवहार भी बढ़ता है; इससे अतिरिक्त मुनाफा लिये बिना भी काफी धन बचने की गुंजाइश रहती है। व्यापारी और साहूकारों को ग्रामदान में शामिल होना चाहिए और ग्रामसभा, ग्रामकोष, सहकारी समितियाँ, ग्राम-भण्डार आदि स्थानीय संस्थाओं के संचालन में और उनके विकास में अपनी बुद्धि, प्रतिभा और अनुभव का लाभ देना चाहिए।

कई जमींदार तो गाँव से बाहर रहते हैं। उनको भी ग्रामदान में शामिल होना चाहिए। ग्रामदान-कानून में इसकी अनुमति है।

अक्सर सवाल उठता है कि शादी-ब्याह में, नुक्ता, श्राद्ध आदि में कैसे क्या होगा? जमीन बेचें नहीं, रेहन नहीं रखें, तो हर कोई यह सारा भार कैसे उठा सकेगा? लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि जमीन बेचकर या रेहन रखकर कर्ज लेना आत्महत्या के समान है। बिनोबाजी ने एक बार एक सुन्दर उपमा दी थी। कोई आदमी एक पहाड़ पर गया था। रात हो गयी। जोरो से ठण्ड पड़ने लगी। उसके पास एक ही कम्बल था। उससे ठण्ड से पूरा बचाव नहीं हो पाता था। उस समय उसे एक बड़िया विचार सूझा। उसने उस कम्बल में आग लगा दी। सेंकने बैठ गया। काफी गरमी मिली। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वह सुख चन्द मिनट ही मिल सका। ज्यों ही कम्बल जलकर राख बन गया, तब पहले से ज्यादा ठण्ड लगने लगी और वह ठिठुरकर मर गया।

शादी, श्राद्ध बगैरह के लिए जमीन बेचना कम्बल जलाकर गर्मी

प्राप्त करने जैसा ही काम है। इससे अगली पीढ़ी को भी जीविका के साधन से वंचित होना पड़ता है। इसलिए ऐसे खर्चों के लिए कोई दूसरा ही जरिया खोजना होगा। फिर ये खर्च भी धीरे-धीरे घटाने होंगे। हमारे जैसे गरीब देश पर ये सारे बोझ बहुत अनुचित हैं। इस बारे में ग्रामदानी गाँव मिलकर विचार कर सकते हैं और ऐसे खर्च कम करने का निर्णय ले सकते हैं। सामूहिक रूप से कई शादियाँ हो सकती हैं। इससे खर्च बचेगा और विशेष आनन्द भी मिलेगा।

कुछ लोगों की कल्पना है कि ग्रामदान होने के बाद सारी जमीन गाँव की हो जाने से सामूहिक खेती ही करनी पड़ेगी, और सारे किसान मिल-जुलकर की तरह हो जायेंगे। इसी कारण वे ग्रामदान को नापसंद करते हैं। यह भय निराधार है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ग्रामदानी गाँवों में जमीन हर एक परिवार में बाँटी जाती है। जबरदस्ती सामूहिक खेती करने की बात नहीं है। ग्रामसभा में सब मिलकर चर्चा करते हैं, सर्वसम्मति से या सर्वानुमति से निर्णय लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता कायम रहती है।

वहाँ, यह हो सकता है कि किसान खुद ही मिल-जुलकर खेती करना चाहें, उसमें उनको लाभ दिखता हो और व्यक्तिगत खेती छोड़कर सामूहिक खेती करने का तय करें। वैसे वे कर सकते हैं।

आर्थिक समता का सवाल बहुत प्रमुख है। जमीन का केवल बीसवाँ हिस्सा बँटता है, तो फिर समानता कैसे होगी? आज तक जो भयंकर विषमता रही है, ग्रामदान के बाद भी वह वैसे ही बनी रहेगी। समता एकदम सधनेवाली चीज नहीं है। वह तो अपने ढंग से आयेगी। इसमें समय लगता है। बिनोबाजी इसे पर्वतारोहण की उपमा देते हैं। ऐसे भी निर्भर पर्वतारोही होते हैं, जो खड़ी चट्टान और पत्थरों पर सीधे चढ़कर चोटी पर पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग इने गिने ही होते हैं। और दूसरी ओर इजीनियर नीचे से चोटी तक मटक बनाते हैं, जिस पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आराम से चलते-चलते चोटी पर पहुँच सकते हैं। यह

रास्ता लम्बा होता है, इसमें जरूर समय कुछ अधिक लगता है, लेकिन यह रास्ता सबके लिए आसान है, सुलभ है। भ्रामदान इसी सड़क के समान है, जो सबको आसानी से चोटी पर पहुँचाती है। इस पर हर कोई चल सकता है और चलते-चलते निश्चित ही मजिल पर पहुँच सकता है।

उसमें पहला काम है, भूमि के एक छोटे हिस्से का वितरण। सुख-दुःख से एक-दूसरे से कधा मिलाकर, परस्पर हाथ बँटाते हुए जीने का आरम्भ यहाँ से होता है। उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जायेंगे। जिनके पास बहुत कम जमीन रह जायगी, उनको दूसरे-दूसरे उद्योग भी दिये जायेंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। बाकी किसान भी अपनी भूमि से अधिकाधिक उपज लेने की कोशिश करेंगे और धीरे-धीरे इस प्रकार कुछ ही वर्षों में अपनी भूमि में कुछ अन्य लोगो को शामिल कर लेने लायक उनकी स्थिति हो जायगी और वे ऐसा करना चाहेंगे भी। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी।

विनोबाजी इस बात की ओर बराबर ध्यान खींचते रहते हैं कि आने-वाली पीढ़ी आर्थिक समता और सामाजिक न्याय के धारे में हमसे अधिक तीव्रता से सोचनेवाली है कम नहीं। हमारे इस काम को लोग अधिक वेग और उत्साह से आगे बढ़ानेवाले हैं। समय की गति हमेशा आगे की ओर रहती है, पीछे मुड़ती नहीं है। इसलिए जल्दी या धीरे यह उद्देश्य प्राप्त होकर रहनेवाला है, क्योंकि ऐतिहासिक परिवर्तन की गति दिन-ब-दिन तेज होती जा रही है।

ग्रामदान-आन्दोलन की स्थिति

ग्रामदान-आन्दोलन का आरम्भ मगरीठ से हुआ । तब वह बहुत छोटा था । बाद में वह बड़ी तेजी से फैला । सन् १९५५ तक उड़ीसा में लगभग एक हजार ग्रामदान हो गये थे । सन् १९५८ तक आंध्र, मद्रास, केरल और महाराष्ट्र में सैकड़ों ग्रामदान हुए थे । इस समय कश्मीर और नागा-लैण्ड को छोड़कर सभी प्रदेशों में ग्रामदान हुए हैं ।

सन् १९५७ में मैसूर राज्य के एलवाल नामक स्थान में एक बड़ी ग्रामदान-परिपद् हुई थी । उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू तथा विनोबाजी के अलावा कांग्रेस, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आदि प्रमुख राजनैतिक पक्षों के नेता भी सम्मिलित हुए थे ।

परिपद् दो दिन तक चली और उसमें सर्वसम्मति से एक निवेदन स्वीकृत किया गया, जिसमें ग्रामदान-आन्दोलन को सब पक्षों ने अपना समर्थन व्यक्त किया था । निवेदन में कहा गया है कि ग्रामदान-आन्दोलन भू-समस्या का सर्वोत्कृष्ट समाधान है और इससे देश की नैतिक तथा भौतिक उन्नति में सहायता मिलेगी । उसने आवाहन किया था कि ग्रामदान-आन्दोलन और सामुदायिक विकास-योजना का घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए ।

सन् १९६१ में विनोबाजी असम गये । वहाँ डेढ़ साल भ्रमण किया । उस अरसे में ९०० से कुछ अधिक ग्रामदान वहाँ मिले । वे असम से इधर आये ही थे कि भारत की सीमा पर चीन का आक्रमण हो गया । उस सघर्ष के सदर्भ में विनोबाजी प्रतिरक्षा के एक अचूक साधन के रूप में ग्रामदान

का महत्व जोरो से समझाने लगे और ग्रामदान की शर्तों में कुछ संशोधन कर दिया, ताकि वह सबके लिए सुलभ हो सके।

इस नये आधार पर बंगाल में तथा अन्य प्रदेशों में भी सैकड़ों ग्रामदान होने लगे। मगरीठ एक साधारण गाँव था, लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र के अधिकतर ग्रामदान आदिवासी क्षेत्र के थे। मद्रास में जो ग्रामदान हुए, वे आदिवासी लोगों के गाँव नहीं थे, बल्कि औसत स्तर के थे। असम के ग्रामदानी गाँव भी गैर-आदिवासी साधारण गाँव थे। इसके बाद पढ़े-लिखे लोगों के अच्छे स्तर के बड़े-बड़े गाँव भी ग्रामदान में मिलने लगे। देश के किसी भी स्थान का कोई भी गाँव ग्रामदान हो सकता है, इसकी सम्भावना स्पष्ट होने लगी।

दिसम्बर '६३ में रायपुर में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। उसमें ग्रामदान, खादी और शान्ति-सेना का 'त्रिविध कार्यक्रम' स्वीकृत हुआ। यह माना गया कि सन् १९६९ में गांधीजी की जन्म-शताब्दी तक त्रिविध कार्यक्रम के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाय कि भारत के सारे गाँवों में 'ग्राम-स्वराज्य' की नींव पड़ जाय, और यही गांधीजी के प्रति वास्तविक श्रद्धाजलि होगी।

गोपुरी (वर्धा) में सब सेवा सघ के अधिवेशन के अवसर पर मई १९६५ में विनोबाजी ने बिहार में ग्रामदान-तूफान खड़ा करने की अपील की। बिहार के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि यदि वे छह महीने में दस हजार ग्रामदान प्राप्त करने का सक्त्प करते हैं, तो वे उनकी मदद में बिहार आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और विनोबाजी ने ११ सितम्बर '६५ को बिहार में प्रवेश किया। बाद में अवधि कुछ बढ़ानी पड़ी और जुलाई '६६ के अन्त तक वहाँ ९,२०० ग्रामदान हो चुके थे।

तूफान-आन्दोलन देशभर में फैला। जोरो से ग्रामदान होने लगे। ७,००० की जगह जुलाई '६६ के अन्त तक २३,००० ग्रामदान हो गये।

अप्रैल १९६६ में बलिया (उ० प्र०) में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। उसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि सन् १९६६ के अन्त तक देशभर में ५० हजार ग्रामदान प्राप्त किये जायें। श्री जयप्रकाशजी ने अपना विश्वास

दिया है और कई जगह तो गैरकानूनी ढंग से बर्माचारियों ने जो पैसा लिया था, वह वापस वसूल कर लिया गया है।

खासकर पिछड़े हुए इलाकों में वहाँ की अर्थ-व्यवस्था पर साहूकारों की बड़ी गहरी पकड़ होती है। वे सामान्यतया बर्जों पर ५० से १५० प्रतिशत तक ब्याज वसूल कर लेते हैं। शुरू शुरू में साहूकारों ने ग्रामदान का विरोध किया, अपने प्रभाव का उपयोग करके उसे तोड़ने का भी प्रयत्न किया। कई जगह तो वे सफल भी हुए, लेकिन अधिकतर गाँवों में ग्रामीण झुके नहीं, डटे रहे। उन्होंने अपना ग्रामकोष बना लिया और इससे उनका आधार मजबूत हुआ। फिर अन्ततः साहूकारों को डीला होता पड़ा। उन्होंने ब्याज की दर घटा दी और गाँववालों के साथ सहयोग करने लगे।

ग्रामदान के बाद निर्माण-कार्य भी शुरू किया गया है। गांधी स्मारक निधि, कस्तूरबा स्मारक निधि, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, असह्य खादी-ग्रामोद्योग-संस्थाएँ, हरिजन सेवक सघ आदि जितनी संस्थाएँ गांधीजी के रचनात्मक कामों में लगी हुई हैं, वे सब ग्रामदानी क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देने लगी हैं, और कई ग्राम समूहों में अपना केन्द्र चला रही हैं। इन केन्द्रों में वे अपनी-अपनी प्रवृत्तियाँ तो चला ही रही हैं और साथ ही अन्य विकास-कार्यक्रमों में भी रुचि ले रही हैं। खादी-संस्थाएँ खादी कार्य कर रही हैं, और कस्तूरबा निधि गाँव की बहनों और बच्चों की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं।

विकास की विविध प्रवृत्तियाँ चलाने के लिए स्वयं ग्रामदानी गाँव के लोगो ने अपने सगठन बनाये हैं। मद्रास में ग्राम-स्वराज्य सहकारी-समितियाँ बनी हैं, और असम तथा उड़ीसा में 'ग्रामदान-सघ' बने हैं। ये संस्थाएँ सामान्यतया प्रखण्ड स्तर की हैं और ग्रामदानी गाँवों के प्रतिनिधि उनके सदस्य हैं। ये सघ सोसाइटी-रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर कराये जाते हैं। दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार के सघों का गठन हो रहा है। मद्रास में इन सघों ने खेती की पैदावार बढ़ाने और बित्री का सगठन करने में बड़ा उपयोगी काम किया है।

गुजरात में सहकारी-समितियाँ काफी यशस्वी रही हैं। वहाँ अनाज आदि सभी वृषि-उत्पादन की बिक्री का पूरा भार उन समितियों ने उठा लिया है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। कोरापुट में छोटे प्रमाण में यह प्रयत्न हुआ है।

एलवाल परिषद् में—सन् १९५७ में—यह निवेदन स्वीकृत हुआ था कि भारत-सरकार की सामूहिक विकास-योजना और ग्रामदान-आन्दोलन में घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए। हाल में सर्व सेवा सघ और सामुदायिक विकास-मशालय के सहयोग से २५ सघन क्षेत्रों की एक योजना हाथ में ली गयी है। प्रत्येक क्षेत्र में सटे हुए कई ग्रामदान हैं, कुल जनसंख्या लगभग ५,००० है और कुल भूमि भी लगभग ५,००० एकड़ है। योजना का मुख्य लक्ष्य वृषि, भुर्गी-पालन तथा पशु-पालन-उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना है।

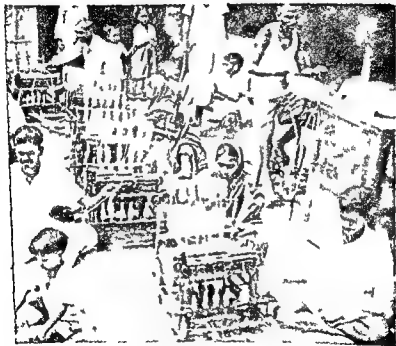
खादी-ग्रामोद्योग कमीशन ने अपनी यही नीति निर्धारित कर ली है कि खादी-कार्य को बढ़ाने का काम आगे से केवल ग्रामदानी क्षेत्रों में ही किया जायगा।

इंग्लैण्ड में 'वार ऑन वाण्ट' नामक संस्था है। पिछड़े राष्ट्रों के गाँवों के विकास के लिए सहायता देना ही उसका एवमात्र उद्देश्य है। इस संस्था ने ग्रामदान-आन्दोलन की ओर स्वयं दिलचस्पी ली और ४०० गाँवों को २४ लाख रुपये की सहायता दी है। औसत एक एक गाँव को ६-६ हजार रुपये मिले हैं। इसके अलावा ग्रामदानी गाँवों में कृषि की सुधरी पद्धति बाखिल करने आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए और भी कुछ सहायता दे रही है। 'वार ऑन वाण्ट' की धनराशि का उपयोग सिंचाई के साधनों में, सहकारी समितियों और छोटे उद्योगों को चालू करने जैसे कामों में किया जा रहा है।

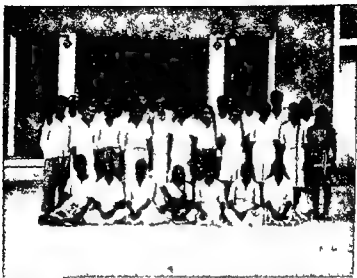
भारत सरकार ने ग्रामदानी गाँवों को अनुदान और ऋण के रूप में देने के लिए एन करोड़ की रकम अलग से स्वीकृत कर रखी है। अभी तक वह धन काम में लेना सम्भव नहीं हो सका है। कई राज्यों में प्रादेशिक सरकारें भी काफी मददगार रही हैं। कुछ राज्यों में ग्रामदान-कानून बने

हैं और दूसरे राज्यों में विधानसभा के सामने बिल लाने का प्रयत्न चल रहा है। मद्रास-सरकार ने एक भारी खम ग्रामदानी गाँवों को ऋण के रूप में देने के लिए निश्चित कर रखी है, जो दूसरा कोई जरिया न रह जाने पर प्राप्त हो सकती है। उड़ीसा-सरकार ने ५०० ग्रामदानी गाँवों के कृषि-सुधार के काम के लिए सहायता के रूप में अब तक २५ लाख रुपये दिये हैं।

यद्यपि ये सारी सहायताएँ काफी बड़ी हैं, फिर भी ग्रामदानी गाँवों की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत ही कम हैं, अपर्याप्त हैं। लाखों की संख्या में जब ग्रामदान हो जाते हैं, तब क्या राज्य-सरकार की, क्या भारत-सरकार की, सब योजनाएँ जड़-मूल से बदलनी होगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता मिल सके। फिर भी गाँवों की अपनी साधन सामग्री का पूरा उपयोग करके गाँव की शक्ति खड़ी नहीं की जाती है, तो सरकार से मिलनेवाली सारी सहायता ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ही होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की एक विशाल सेना जरूरी है, जो गाँवों में बराबर घूमती रहे और लोगों को जगाती रहे। ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बन रहा है। दान्ति-सेवा-दल के द्वारा वह काम होगा। उड़ीसा में पिछले साल इस प्रकार के २८ शिविर हुए, जिनमें १,५०० व्यक्तियों ने भाग लिया। इस वर्ष देशभर में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ●



नयी औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बबर परिश्रमालय



शांतिसेना शिविर, बहमदाबाद के शिविरार्थी



नेफ़ के एक शांतिकेन्द्र में

: ७ :

खादी

सन् १९१९ में गांधीजी ने भारत की गरीबी को जब अपनी आँखों से देखा, तब उन्हें खादी-प्रवृत्ति को पुनरुज्जीवित करने की बात सूझी । वह आन्दोलन धीरे-धीरे विकसित होता गया और उसके साथ-साथ दूसरे ग्राम-उद्योग जुड़ते गये । खादी अहिंसक समाज-रचना का प्रतीक और अहिंसक अर्थ-नीति की केन्द्रबिन्दु बनी ।

खादी-कार्य को बढ़ाने और फैलाने के लिए सन् १९२५ में अखिल भारत खरखा संघ की स्थापना हुई और ग्रामोद्योगों का पुनरुत्थान करने की दृष्टि से सन् १९३५ में अ० भा० ग्रामोद्योग संघ गठित हुआ । इन दो अखिल भारतीय संगठनों के अलावा सैकड़ों स्थानीय संस्थाएँ थी, जो इन्हीं ग्रामों में लगी हुई थी । सन् १९४६ तक देशभर में खादी और ग्रामोद्योगों का उत्पादन लगभग १ करोड़ ६ लाख रुपये से कुछ अधिक था ।

यह स्वराज्य के पहले की बात है । स्वराज्य के बाद भारत-सरकार ने इन्हीं ग्रामों को बढ़ावा देने के लिए खादी-ग्रामोद्योग कमिशन की स्थापना की । इसे सलाह-भरामस देने के लिए दूसरा एक मण्डल (बोर्ड) भी है । इसी ग्राम के लिए प्रत्येक राज्य में अलग-अलग बोर्ड भी है । इनके अलावा देशभर में छोटी-बड़ी लगभग दो हजार से अधिक संस्थाएँ हैं, जो खादी और ग्रामोद्योग के ग्राम के लिए ही समर्पित हैं । सन् १९६५ में खादी का कुल उत्पादन २०.९८ करोड़ रुपये का हुआ और '६६ में २१.१२ करोड़ रुपये का । ग्रामोद्योगों का उत्पादन सन् '६५ में ३५.५५ करोड़ रुपये का और सन् '६६ में ३४.७७ करोड़ का हुआ । इन सब प्रवृत्तियों में लगभग १७०

करोड़ की पूंजी लगी है। इसमें अधिकांश हिस्सा केन्द्रीय और राज्य सरकारों का है।

वतबंदे, बुनकर और अन्य कारीगर कुल मिलकर लगभग २६ लाख लोग इन उद्योगों में, कुछ पूरी और कुछ आंशिक रोजी पा रहे हैं।

खादी को समझने के लिए कुछ और तथ्यों को देख लेना भी उचित होगा।

इस समय भारत की जनसंख्या लगभग ४७ करोड़ है। इसमें से ८५ प्रतिशत संख्या खेती पर निर्भर है। इतने लोगों को खेती में बारह महीने पर्याप्त रोजी नहीं मिल पाती है। लगभग आधा समय वे बेकार रहते हैं। स्पष्ट है कि आधा समय बेकारी में बितानेवाले लोग किसी कदर अच्छी स्थिति में रह नहीं सकते। खाली समय के लिए उन्हें कुछ-न-कुछ घधा मिलना चाहिए। अथवा, इसके बजाय क्या यह नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को खेती से हटा लिया जाय और उन्हें कोई दूसरा ही काम दे दिया जाय ?

दूसरे देशों में खेती पर कम-से-कम लोग रूके होते हैं। जापान में केवल ४० प्रतिशत हैं, अमरीका में १५ प्रतिशत हैं। तो भारत में भी वैसा प्रयत्न क्यों न किया जाय ?

स्वराज्य के बाद हमारे नेताओं ने सोचा कि शहरों में बड़े-बड़े कल कारखाने खोले जायें और लोगों को देहातो से बाहर ले जाकर वहाँ काम दिया जाय। इसमें उनका विशेष भरोसा था। लेकिन क्या हुआ ?

सन् १९५०-५१ और १९५१-६० के बीच हमारे देश में काम करने योग्य लोगों की संख्या ३ करोड़ २० लाख बढ़ी, यानी इतने लोगों को नये सिरे से रोजी देने की जरूरत पड़ी। इसी अवधि में जो बड़े उद्योग खड़े किये गये, उनमें जरिये केवल ११ ८ लाख लोगों को ही काम मिल सका। यह ३ करोड़ २० लाख लोगों का केवल ४ प्रतिशत होता है। तो बाकी ९६ फीसदी लोगों को उनके अपने भाग्य पर यानी मुख्यतया खेती के भरोसे पर छोड़ दिया गया। इस संख्या में उन करोड़ों का हिसाब शामिल नहीं

है, जो सन् '५० के पहले से ही बेकार थे और इस अवधि में भी बेकार ही रहे हैं।

लोग जब २० गुना बढ़ गये हैं, तब उद्योगों को भी २० गुना क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता ?

इसीलिए बढ़ा नहीं पाते कि उसके लिए धन नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिये, एक कपड़े की मिल खोलनी है। उसमें लगभग एक करोड़ रुपये लगते हैं। उसमें केवल ५ सौ लोगों को काम दे सकते हैं। इसका मतलब यह कि एक व्यक्ति को काम देने के लिए २० हजार रुपये की पूंजी लगानी होती है। अर्थात् ऐसे कारखानों के जरिये देश के ४ करोड़ बेकारों को काम देने की बात सोचे, तो इसके लिए ८०,००० करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। आज देश के सभी बड़े उद्योगों और व्यवसायों में जो पूंजी लगी है, वह ५,००० करोड़ से भी कुछ कम है।

इसलिए इन सबको काम देने के लिए कोई दूसरा ही उपाय सोचना होगा। व्यावहारिक उपाय यही हो सकता है कि छोटे-छोटे उद्योग फैलाये जायें, जिनमें कम-से-कम पूंजी लगती हो और जिनको चलाने में मनुष्य-शक्ति का उपयोग मुख्य रूप से हो सके। अम्बर चरखे के द्वारा एक व्यक्ति को काम देना है, तो उसमें लगभग २५० रु० की पूंजी लगती है। हाथ-करघे के जरिये काम देना हो, तो लगभग ३०० रु० की पूंजी लगेगी। इस तरह के सादे और छोटे छोटे औजारों के द्वारा करोड़ों लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ण या आंशिक रोजी दी जा सकती है।

यह सही है कि छोटे उद्योगों में पैदा होनेवाले माल बड़े कारखाने के माल से कुछ महँगे पड़ते हैं। एक-एक अदद पर, कपड़े के एक-एक मीटर पर, तेल के एक-एक किलोग्राम पर अधिक थम लगना है। लेकिन इसकी ओर देखने की एक और भी दृष्टि है।

एक गाँव लीजिये, जिसकी आबादी ५०० है। एक व्यक्ति के पीछे सालाना २० रुपये का कपड़ा मान लें, तो उस गाँव में सालभर में कुल १० हजार रुपये का कपड़ा जरूरी होगा। इसे खरीदने के लिए वे धान, गेहूँ, दाल आदि

अपनी खेती की पैदावार बेचकर पैसा लाते होंगे । मान लीजिये, वे अपनी फुरसत के समय का उपयोग करने लगते हैं और उस समय अपना कपड़ा स्वयं बनाने लगते हैं, तो गाँव में १० हजार रुपये की बचत हो जाती है । उसमें से कपास का दाम घटा दें तो लगभग ७,५०० रुपये की बचत साफ है । गाँव सालाना लगान के रूप में जो रकम चुकाता होगा, उससे यह रकम सात-आठगुना अधिक है ।

इसी तरह चीनी, तेल, साबुन, जूता, कागज आदि निर्योपयोगी चीजों को एक-एक करके लेते जायें, जिनके लिए कच्चा माल गाँव में मिल सकता है । उसका हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि इन उद्योगों को चलाने से गाँव कितनी बड़ी धनराशि की बचत कर सकता है ।

यह सच है कि कइयों के पास पूरा काम है, उनको पूरक उद्योगों की आवश्यकता नहीं है । वे कह सकते हैं कि “हमें तो सभी चीजें खरीदनी होंगी । सब हम मंहंगी खादी क्यों खरीदें ? उससे हम नुकसान में रहेंगे ।”

आज लाखों लोग बेकार हैं, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किये गये माल को खरीदनेवाले बहुत कम हैं । उन बेकारों में कई तो भूखों मरने की स्थिति में हैं और उनकी राहत पहुँचाने के लिए सरकारों को करोड़ों रुपये दान के रूप में बाँटना पड़ता है । यह धन लोबों की जेब से ही जाता है । जो राष्ट्र अपने को समाजवादी कहते हैं, वहाँ यह अनिवार्य माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजी, रोटी और कपड़ा मिलना ही चाहिए, जैसा कि इंग्लैण्ड, अमरीका आदि में हो रहा है । लेकिन यह हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार मुफ्त में पैसा बाँटने के बजाय उनसे कुछ काम बराबर, उनकी पैदा की हुई चीजों को दो पैसे अधिक देकर खरीदना अच्छा है । काम से आदमी का मान बढ़ता है । मुफ्त की ख़राब मान घटाती है ।

इसीलिए सर्वोदय-आन्दोलन का कहना है कि ऐसे लोगों को निर्मित वस्तुओं को जरा अधिक दाम देकर खरीदें । दाम में जो अधिक पैसा देना पड़ता है, इसे दान समझ लीजिये । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम यह निश्चय करें कि सरकार ‘डोल’ देकर, मुफ्त में बेकारों को पैसा

दे, तो उसके लिए भी किसी नये 'वर' के रूप में हमीको कुछ रकम देनी होगी।

सर्वोदय-आन्दोलन समाज को करुणा और सेवा का आधार देना चाहता है। जब हम देखते हैं कि लोग दुःखी हैं, तब उसका हम पर प्रभाव पड़ता है और हम उनकी कुछ-न-कुछ सहायता करते ही हैं। यह है करुणामूलक हार्दिक सेवा। जब सभी ऐसा करने लगते हैं, तो समाज मानवता से समृद्ध होगा, मानवीय भावना से सम्पन्न होगा।

इस प्रकार से खादी-ग्रामोद्योगों को सहारा देना भूदान-आन्दोलन की तरह, सेवा का ही एक रूप है।

बुनियादी सिद्धान्तों को हानि न पहुँचाते हुए खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं को सस्ता करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी प्रयत्न का एक परिणाम अम्बर चरखे का आविष्कार है। साधारण चरखे से छह-सात-गुना अधिक उत्पादन अम्बर चरखे द्वारा होता है। इसी प्रकार दूसरे ग्रामोद्योगों में भी सुघरे औजारों को दाखिल किया गया है। इन उद्योगों की कई प्रक्रियाओं में बिजली-शक्ति का भी उपयोग किया जाता है। इसमें इतना ध्यान रखा जाता है कि बिजली लगाने के कारण कोई व्यक्ति बेकार न हो जाय, किसीकी रोजी छिन न जाय, बल्कि मनुष्य की शक्ति में वृद्धि हो सके और उसे अधिक सक्षम और अधिक उत्पादक बनाया जा सके। सुघरे करघों से भी अधिक उत्पादन होने लगा है। अधिकाधिक उत्कृष्ट औजारों की खोज और प्रयोग बराबर जारी है।

फिर भी ज्यादातर लोगों को ये सब साधन बड़े महँगे पड़ते हैं। इसलिए सरकार से सहायता माँगी गयी थी कि वह खादी पर १९ प्रतिशत की सहायता दे, ताकि खरीदार को एक रुपये की खादी ८९ पैसे में ही मिल सके। सरकार ने वह सहायता स्वीकार की और दी भी गयी। तब भी खादी मिल के बपड़े से महँगी ही पड़ती थी। फिर भी देश में खादी खरीदने-वाले कम नहीं हैं। आज भी १५-१६ करोड़ रुपये की खादी खपती है। लेकिन यह सागर में बूंद के बराबर है। खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा

लगभग ३० लाख बतबैये, बुनवर और अन्य बारीमरो को रोजी मिल रही है। संजिना देश में इससे कम-से-कम २० गुना अधिक बेकार पड़े हैं, जिन्हें काम की आवश्यकता है। खादी में ही इन गवनों काम देना हो, तो खादी-उत्पादन का आज से गंवाड़ा गुना बढ़ाता होगा।

आज तक खादी और ग्रामोद्योग प्रवृत्तियाँ जो पंथी हैं, यह गुठ्ठीभर स्वांगी कार्यकर्ताओं के प्रयास से फैली हैं। लेकिन इन्हीं देश के प्रत्येक गाँव में फैलाना हो, तो यह सभी सम्भव होगा, जद गाँववाले स्वयं इसे अपने हाथ में लेते हैं।

इसी हेतु से दो साल पहले विनोबाजी की राय के अनुसार खादी-कार्य की नीति और पद्धति में एक परिवर्तन किया गया। अब तो सभी गाँवों को अपनी-अपनी खादी घना लेने का महत्व समझ लेना चाहिए। खादी पर जो सहायता दी जाती थी, वह अब 'मुपत बुनार्द' योजना में बदल गयी है।

इस योजना के अनुसार जितना भी हाथ-बटा सूत होता है, उसे बुनने का पूरा धर्च सरकार दे देती है। इसका अर्थ यह कि जो किसान खुद बपास पैदा कर लेता है और फुरसत के समय में बात लेता है, उसको अपने बपड़े के लिए सबद एक पैसा भी धर्च नहीं करना पड़ता।

खादी के इस नये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और फैलाने के लिए निर्दिष्ट ही ग्रामदानी गाँव अनुसूल क्षेत्र है। खादी और ग्रामोद्योगों के बिना ग्रामदानी गाँवों की अर्थ-रचना में आमूल परिवर्तन असम्भव है। त्रिविध कार्यक्रम में केवल खादी का नाम आया है, लेकिन वह दूसरे सभी ग्रामोद्योगों का प्रतीक है। उन उद्योगों का महत्व जरा भी कम नहीं है।

प्रत्येक ग्रामसभा को सवत्स्य करना चाहिए कि एक-डेढ़ साल के अन्दर वह गाँवभर की जरूरत का कपड़ा स्वयं बना लेगी। देश में खादी-काम करनेवाली अनेक संस्थाएँ हैं। उस उस क्षेत्र की संस्था ग्रामसभा को काम शुरू करने में आवश्यक सहायता अवश्य कर सकेगी।

५०० की आबादीवाले बिसी गाँव की मिसाल लें, तो जैसा पहले कहा गया, बाहर से वस्त्र न खरीदने के कारण ७,५०० रुपये की बचत तो

होती ही है, उसके अलावा लगभग २,००० रुपये बाहर से गाँव में आ सकते हैं, जो बुनाई-मदद के रूप में बुनकरों को खादी-प्रामोद्योग कमीशन देता है।

गाँव में यदि कोई बुनकर नहीं है तो बाहर से एक बुनकर-परिवार लाकर बसाया जा सकता है, या गाँव के ही किसी व्यक्ति को बुनाई सिखा सकते हैं, ताकि वह उस धंधे को अपना ले। इसके लिए आर्थिक सहायता या तकनीकी मदद खादी-प्रामोद्योग कमीशन की ओर से दी जाती है। ■

खादी का व्यापक महत्व

हमारे देश को तबाह करनेवाली दो भयंकर बीमारियाँ हैं—नित्य बढती हुई महँगाई और मुनाफाखोरी । खादी और ग्रामोद्योग इनको रोकने में बड़े सहायक हो सकते हैं । महँगाई का एक कारण यह है कि हमारी सरकार ने बड़े-बड़े उद्योग-धद्ये, रेलवे-कारखाने और इस्पात-कारखाने खोलने में बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर दी है । ये सब उद्योग देश के लिए आवश्यक जरूर हैं, लेकिन देश को उनका प्रत्यक्ष लाभ तुरन्त नहीं, कई वर्षों बाद मिलता है । उससे पहले उनसे ऐसी कोई चीज पैदा नहीं होती, जिसे लोग बाजार में जाकर खरीद सकें । लेकिन उनमें जो धन धर्च होता है, वह मजदूर, क्लर्क, कर्मचारी, ठीकेदार आदि अनेक लोगों के पास पहुँचता है, और वे उस धन से कई सामान खरीदना चाहते हैं । इस प्रकार पैसे का चलन तो बढ जाता है, लेकिन उससे खरीदने योग्य पदार्थ तो बढते नहीं हैं । यही महँगाई है ।

इसे दूर करने का एक यही मार्ग है कि नित्योपयोगी चीजों का उत्पादन बढाया जाय । ग्रामोद्योगों के द्वारा ही यह काम अधिक कारण हो सकता है । पिछले प्रकरण में हमने देखा है कि देश में बरोहो ऐसे लोग हैं, जिन्हें पूरे या आंशिक काम की आवश्यकता है, लेकिन साधन होते हुए भी वे बेकार हैं । इन सब लोगों की जो दक्षिण बेकार जा रही है, उसका हिसाब लगाया गया है और बताते हैं कि वह दक्षिण पूरा समय काम करनेवाले लगभग १० करोड़ लोगों की दक्षिण के बराबर है । रोज की औसत मजदूरी कम-कम १ रुपया माना जाय तो सालभर में लगभग २५ तो बरोह रुपया की हानि देश को हो रही है ।

यह रकम बहुत बड़ी है। जैसा पहले कहा गया है, एकमात्र खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा ही इतने लोगों को काम देना सम्भव है। उन्हें व्यापक रूप से ठीक ढंग से फैलाया जाय तो हजारों-करोड़ों गुना उत्पादन बढ़ सकता है और बराबर बढ़ती हुई महँगाई को निश्चित रूप से रोका जा सकता है।

महँगाई का दूसरा कारण है मुनाफ़ाखोरी। कपड़ा, चीनी, तेल, साबुन आदि सब चीज़ें बनानेवाले कारख़ाने निजी उद्योगपतियों के हाथ में हैं। उन वस्तुओं का व्यापार भी निजी ही है। सहज ही ये मालिक लोग भरसक अधिकाधिक मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं। इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न सरकार करती है, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा है। बढ़ोतरी लागू करते हैं, तो उसका भी अधिकार मुट्ठीभर अधिकारियों के हाथ में ही रह जाता है, इससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ती ही है।

सरकार ने लोहा-इस्पात, बिजली और यन्त्र-सामग्रियों आदि के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है। क्या नित्योपयोगी वस्तु के कारख़ानों का भी राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए? लेकिन इस तरह के राष्ट्रीयकरण या सरकारी मालिकी से सरकार के हाथ में बहुत सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है, और अत्यधिक शक्ति का एकत्र होना बड़ा भयानक है। तिस पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो व्यवस्था राष्ट्रीकृत उद्योगों की होगी, वह पूरी विश्वसनीय ही होगी, ऐसा नहीं है। उनमें लापरवाही और अक्षमता बहुत है।

इसका उपाय यही है कि नित्योपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, दोनों सीधे जनता के हाथ में होना चाहिए। यहाँ फिर वही खादी और ग्रामोद्योग आते हैं। ग्रामीण लोग अपनी ग्रामसभा या सहकारी समिति के द्वारा उत्पादन और वितरण की व्यवस्था बैठ सकते हैं। ऊँचे स्तर पर, ऐसी ग्रामसभाओं और स्थानीय सहकारी समितियों के संगठन, संघ या फेडरेशन बनाये जा सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति का नियंत्रण वास्तव में जनता के हाथ में आता है। तब आज के निजी व्यवसायियों और

उद्योगपतियों को जनता के इन सगठनों की नीति के अनुसार अपने को बदलने के लिए विवश होना ही पड़ेगा ।

पूँजीवादी शोषण को खतम करने का यही कारगर उपाय है । जैसा कि विनोबाजी कहते हैं, ये साम्यवादी और समाजवादी लोग पूँजीवाद का समाप्त करने की बात तो बरते हैं, लेकिन उनके द्वारा तैयार किये गये माल को काम में लेकर उन्हींको शोषण दे रहे हैं । खादी प्रामोद्योगों का तो यह प्रयत्न है कि उस पूँजीवाद को मिटा ही दिया जाय ।

आधुनिक काल में लोगों की प्रवृत्ति भारी शहरों में बड़ी सड़ियाँ में आ बसने की हो गयी है । कई पाश्चात्य राष्ट्रीयों में ८५-९० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं । इन शहरों के कारण कई नयी नयी पेचीदा समस्याएँ पैदा होती हैं । उनमें अपराध और अनीति फैलती है । सफाई, पानी आदि की व्यवस्था भी बड़ी कठिन हो जाती है । वहाँ बड़ी भीड़ रहती है, स्वास्थ्य विगड़ता है । लोगों को ताजा हवा और धूप मिलती नहीं । आजकल तो आवागमन भी एक समस्या बन गयी है । सबको घर बेहद भीड़ बनी रहती है ।

देहातों में अनेक प्रकार की सुविधाएँ हैं । वहाँ प्रत्येक आदमी गाँव के हरएक को जानता है । वे एक दूसरे की मदद आसानी से कर सकते हैं । खुला आकाश ताजा हवा और धूप वहाँ भरपूर है । अपराध और अनीति जैसी गम्भीर समस्याएँ वहाँ आ नहीं सकती । लेकिन गंदगी, गरीबी, बेकारी और एवान्त के कारण उद्यमशील लोगों का मन वहाँ नहीं लगता, वे शहरों में जाकर अपनी तबदीर आजमाने का प्रयत्न करते हैं ।

सर्वोदय का लक्ष्य गाँवों को टूटने से बचाना है और उन्हें सदाकत और पुनरुज्जीवित करना है । शहरों में अमुक कुछ सुविधाएँ हैं, और लोग उनको देखकर ही शहर की ओर आकृष्ट होते हैं । लेकिन वे सुविधाएँ आज गाँवों में भी प्राप्त हो सकती हैं और गाँवों को वे सुविधाएँ प्राप्त करनी भी चाहिए । गाँवों को साफ रख सकते हैं । वहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय आदि बना सकते हैं । सबके अच्छी हो जायें, तो गाँव बाहरी

दुनिया से दूर नहीं पड़े रहेंगे । गांवों में टेलीफोन और रेडियो पहुँच सकते हैं, और उनके द्वारा गांव बाहर से संपर्क रख सकते हैं ।

आज शहरों की समृद्धि बड़े-बड़े उद्योगों पर निर्भर है । सामान्यतया नये उद्योग सभी शहरों में खड़े होते हैं और उनके कारण शहर बड़े बनते जाते हैं । सर्वोदय चाहता है कि उद्योग गांवों में खड़े हों और फैलें । गांवों में जब उद्योग चलने लगेंगे, तब गांव अधिक समृद्ध होंगे । छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के ही समान समर्थ और सक्षम हो सकते हैं । कई गांवों में आज बिजली पहुँच गयी है । अगर सबके सब गांवों में बिजली पहुँचे, जल्दी पहुँचे, तो ग्राम-उद्योगों की कई प्रक्रियाओं में उसका उपयोग किया जा सकेगा । इससे मनुष्य पर आज जो अमानुषी भार पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा । अधिक पैदावार बढ़ानेवाले औजारों का निर्माण हो सकता है, पोष्य हो सकता है, प्रयोग हो सकता है और गांवों में उन्हें चालू कर सकते हैं । ग्रामीण और क्षेत्रीय योजना ऐसी बनायी जा सकती है कि इन औजारों के कारण गांव का एक भी आदमी बेकार न रहे, विषमता पैदा न हो और शोषण न हो ।

गांवों में लोग अपने घरों में या घर के ही आसपास मनोहर वातावरण में काम करते हैं । काम करने में उनको अधिक उत्साह आता है । और आसानी से वे विश्राम भी कर सकते हैं । वे उस बेहद परेशानी, चिंता और तनाव से बचेंगे, जिसके शहरी लोग शिकार बने हुए हैं । घर में और दुनिया में शान्ति स्थापित करने में यह एक बहुत बड़ा आवश्यक तत्व है ।

इस प्रकार खेती और अधिकांश गांवों में उद्योग रहेंगे । और बिल्कुल थोड़े से बड़े उद्योग शहरों में रहेंगे । इस्पात, रेलें, जहाज आदि बड़े उद्योग तो शहरों में ही चलाने होंगे । लेकिन उनका आकार और उनकी सख्या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए ।

जिस अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार ग्रामीण और छोटे उद्योगों की प्रधानता होती है, उसे 'विवेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था' कहते हैं । जिस प्रशासन-पद्धति में ग्रामसभा बुनियाद रहेगी और अपने प्रशासन के अधिकाधिक भाग ग्रामो

के हाथ में रहेंगे, उसे 'विकेन्द्रित राज्य-व्यवस्था' कहते हैं। इन दोनों के आधार पर विकेन्द्रित समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता और विकास का पूरा अवसर देने का आश्वासन एकमात्र विकेन्द्रित समाज ही दे सकता है। इसीलिए सर्वोदय में इसकी अनिवार्यता मानी गयी है।

सर्वोदय केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि समूचे विश्व के लिए है। आखिर दुनिया को एक होना है। बिनोबाजी की यह कल्पना है कि एक सिरे पर रहेगा स्वायत्त और स्वशासित गाँव और शहर, तथा दूसरे सिरे पर रहेगा विश्व। इन दोनों के बीच प्रदेश, देश आदि जितने भी हिस्से होंगे, वे सब प्रशासन की सुविधा की अलग-अलग इकाइयाँ ही रहेंगी, उनका इससे अधिक महत्त्व नहीं रहेगा। सारे विश्व के लोग जाति, वंश, भाषा, धर्म, विचार आदि सभी भेदभाव भूलकर एक महान् परिवार बनाकर रहेंगे।

ग्रामदान, छादी और शान्ति-सेना विश्व के उस भव्य भविष्य की बुनियाद डाल रही है। अब तक हमने शुरू के दो कार्यक्रमों के बारे में विचार किया। अब अगले प्रकरण में तीसरे कार्यक्रम पर विचार करेंगे। ●

शान्ति-सेना का आदर्श

३० जनवरी १९४८ का दिन, शाम के ५-१० का समय । नयी दिल्ली में बिड़ला-भवन के आँगन में गांधीजी तेजी से प्रार्थना-स्थल की ओर बढ़े जा रहे थे । उन्हें जरा देर हो गयी थी, क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं की गम्भीर चर्चा में लगे हुए थे, इसलिए जल्दी में थे ।

गांधीजी मंच पर पहुँचने ही वाले थे कि इतने में उन्हें तीन गोलिएँ लगीं और वे घराशायी हो गये ! न उनके मुँह से कोई कराह निकली, न हृत्कारों के प्रति आक्रोश । उनके ओठों से यही एक शब्द निकला—
'हे राम !'

इस प्रकार, जैसा कि विनोबाजी ने बाद में भावनाभरे शब्दों में व्यक्त किया : "गांधीजी प्रथम शान्ति-सैनिक थे, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए प्राण त्यागे । उन्होंने एक सेनापति के नाते आदेश दिया और सैनिक के नाते उस पर अमल किया ।"

शान्ति-सेना ऐसे लोगों का एक समूह है, जो समाज के सभी सघर्षों और तनावों को शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने तथा हिंसक उपद्रवों को शान्ति से शान्त करने के लिए कटिबद्ध हो । यह विचार कई वर्ष पहले गांधीजी ने प्रकट किया था । उन्होंने कहा था :

"कुछ समय पहले मैंने ऐसे स्वयंसेवकों की एक सेना बनाने की सज्जगी रखी थी, जो दंगे—चासकर साम्प्रदायिक दंगे—को शांत करने में अपने प्राणों तक की बाजी लगा दें । विचार यह था कि यह सेना पुलिस का ही नहीं, बल्कि फौज तक का स्थान ले ले । यह बात बड़ी महत्वाकांक्षा की मालूम पड़ती है, शायद यह असम्भव भी साबित

हो। फिर भी कांग्रेस को अगर अहिंसात्मक लड़ाई में कामयाबी हासिल करनी हो, तो उसे ऐसी परिस्थितियों का शान्तिपूर्वक अहिंसा से सामना करने की अपनी शक्ति बढ़ानी ही चाहिए।”

स्वराज्य से पहले भारत में जो भयानक साम्प्रदायिक दंगा फूट पड़ा और देश के विभाजन के बाद जिसने अत्यन्त उग्र रूप धारण किया, तब गांधीजी उस साम्प्रदायिक उत्तेजना की अग्नि को शान्त करने के प्रयत्न में जी-जान से लग गये और उसी प्रयत्न में कुरवान हो गये !

उनकी सहादत ने उस समय भाई-भाई के उस भीषण संघर्ष को शान्त तो कर दिया, लेकिन भारत में उसने बाद अनेक प्रकार से हिंसक उपद्रवों का सिलसिला बराबर चला आ रहा है। भाषा के प्रश्न पर, धर्मपन्थ के प्रश्न पर, राज्यों के प्रश्न पर, इसी तरह कई कारणों से वहाँ हिंसक उपद्रव हुए हैं। मजदूर-आन्दोलनों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों में भी हिंसा हुई है, पुलिस का या सरकारी निर्णयों का बदला लेने तक की नौबत आयी।

ऐसे उपद्रवों को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की मदद में सेना को भी बुलाना पड़ा। इन उपद्रवों तथा पुलिस की गोलियों के कारण कई जानें गयीं। सम्पत्ति की हानि भी काफी हुई। ऐसी सारी आन्तरिक अशान्तियों के कारण देश कमजोर होता है और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। देश की एकता के लिए भी यह बड़ा घातक है। पुलिस पर जो अत्यधिक खर्च करना पड़ रहा है, यह देश की सम्पत्ति का अपव्यय ही है। ऐसे सब मामलों में अपने ही नागरिकों के खिलाफ फौज का उपयोग करना पड़ता है। यह बड़े घेद की बात है।

समाज को अनुशासन में रखने के लिए पुलिस और सेना का हमेशा उपयोग करते रहना त्रमश पुलिस और सेना की शक्ति और महत्त्व को बढ़ावा देना है। इससे लोकतन्त्र की बुनियाद धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से क्षिणिल होती जाती है और उसके अस्तित्व को ही खतरा पैदा होता है। लोगों को हिंसा की आदत पड़ जाती है और लोकतन्त्र में विश्वास खत्म हो जाता है।

इसलिए हमारे देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सारे विवाद और सघर्षों का समाधान शांतिमय उपायों से ही किया जाय। जब तक जनता स्वयं ऐसे शांतिमय तरीकों की आदी नहीं होती है तब तक इसका प्रारम्भ करने के लिए त्यागी और सेवान्वीत सेवकों के एक समूह की आवश्यकता रहेगी।

ऐसे उपद्रवों के कारणों की छानबीन करने लगते हैं, तो अनेक बातें दिखाई देती हैं, फिर भी विशेष महत्त्व के दो प्रकार के कारण हमारा ध्यान खींचते हैं। एक प्रकार के उपद्रवों के पीछे जाति, धर्म और भाषाई समूहों के मन में अरसे से गहरा बसा हुआ सशय और द्वेषभाव होता है। बम्बई इतिहास में ऐसी घटनाएँ हो गयी हैं, जिनके कारण इस तरह के सशय और द्वेष पैदा हुए हैं। लेकिन आम तौर पर उन बातों का आज के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

उदाहरण के लिए साइप्रस में ग्रीक और तुर्की लोगों में, या मध्यपूर्व देशों के अरब और यहूदियों में आपसी द्वेष और शका की भावना होती है, तो इसी सघर्ष में उनकी बहुत बड़ी शक्ति खर्च हो जाती है। इससे कारण वे 'सबके हित' की किसी भी प्रवृत्ति में मिल-जुलकर शक्ति लगा नहीं पाते और आधुनिक विज्ञान ने जो-जो विशाल सुविधाएँ निर्माण की हैं, उनका लाभ उठा नहीं पाते। यही बात भारत में पिछले दिनों स्वर्ण और धुद्र भावना के कारण जो दंगे और उपद्रव हुए, उन पर भी लागू है।

दूसरे प्रकार के उपद्रवों के कारण भिन्न कोटि के हैं। हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत-सी अयायपूर्ण बातें भरी हुई हैं। कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों के हाथ में हजारों लोगों को काम देने की शक्ति और जीविका के साधनों का हक केन्द्रित हो गया है, कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और जो छोटे या निचले हैं, उनको अपने बराबर मानने को तैयार नहीं होते। इस तरह की आगिनित विषमताएँ हैं। इसके अलावा आर्थिक रोग भी बहुत हैं, जिनके कारण अन्न सख्त, महँगाई

आदि बण्ट पैदा होते हैं। इन सबके कारण लोगों को बड़ी बठिनाई का सामना करना पड़ता है।

लोग जब इन अन्यायों और विषमताओं को सहन नहीं कर पाते हैं या ये दुःख बरदाश्त नहीं कर पाते हैं, तब विद्रोह कर बैठते हैं। अबसर इन दुःखों का सामना शान्तिमय ढंग से कैसे किया जाय, यह वे जानते नहीं हैं या फिर उनमें उतना धीरज नहीं रहता। इसी कारण हिंसाकाण्ड और उपद्रव फूट पड़ते हैं।

आजकल इनका एक जागतिक पहलू भी है। ससार में बड़ी राष्ट्र ऐसे हैं, जहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दोषपूर्ण है, और उसके कारण बहुसंख्य जनता को गरीबी और भूख का शिकार होना पड़ रहा है। यद्यपि विज्ञान के कारण मानव-कल्याण की विशाल सम्भावनाएँ खुल गयी हैं, तथापि उन सम्भावनाओं का लाभ तभी प्राप्त हो सकेगा, जब ये अन्याय और पुरानी पद्धतियाँ बदल जायेंगी।

अधिकांश लोगों के मन में दृढ़ धारणा बनी हुई है कि इन अन्यायपूर्ण पद्धतियों को खत्म करने के लिए एक जागतिक क्रान्ति की आवश्यकता है। उनका विश्वास है कि वह क्रान्ति हिंसक ही होनी चाहिए और उसके कारण विश्व-युद्ध छिड़ जाय तो भी हर्ज नहीं।

यद्यपि पिछले जमाने में कई सामाजिक क्रान्तियाँ हुई हैं, जिनके कारण विश्व-युद्ध की नीबट नहीं आयी, लेकिन आज विश्व की परिस्थिति ऐसी है कि वही कोई सघर्ष छिड़ता है, तो उससे विश्व-युद्ध का खतरा हो सकता है। और आज यदि तीसरा विश्व-युद्ध होता है तो उसमें अणु-अस्त्रों का प्रयोग जरूर हो सकता है और सारी मानव-संस्कृति मिट्टी में मिल सकती है।

इसलिए दूसरे लोग युद्धों और सघर्षों से डरते हैं तथा शान्ति को प्राथमिकता देते हैं। वे हर कीमत पर, यहाँ तक कि अन्याय और दुःखों को आज की हालत को ज्यों-का-त्यों बरदाश्त करते हुए भी शान्ति बनाये रखना पसंद करते हैं।

इससे ससार के सामने एक द्वन्द्व खड़ा होता है—शान्ति या युद्ध ?

लेकिन दु खी सत्तार आज शान्ति और शान्ति दोनों चाहता है । सत्तार को ये दोनों मिल सकते हैं, यदि हम शान्तिमय शान्ति कर सकें अथवा अमुक प्रकार की शान्तिकारी शान्ति कायम कर सकें । वैसे कोई समाधान क्या हमारे पास है ? इस प्रश्न के उत्तर पर सत्तार का अविष्य निर्भर है ।

सन् १९५१ में जब विनोबाजी तेलंगाना के पीडित क्षेत्रों में गये, तब ऐसा ही एक समाधान, इसी प्रकार का उत्तर उनको मिला । वहाँ हिंसक उपद्रव फूट पड़ा था । उस उपद्रव के केन्द्र में भूमि की समस्या थी । वहाँ कुछ लोगों के हाथ में बेहद जमीन थी और बाकी अधिकांश लोग बेजमीन थे । एक गाँव में विनोबाजी की अपील पर जमींदार रामचन्द्र रेड्डी ने स्वेच्छा से भूमिहीनों के लिए १०० एकड़ जमीन दान के रूप में दी तो विनोबाजी को भूमि-समस्या का शान्तिमय समाधान मिल गया । इस अल्प आरम्भ से विद्याल भूदान-आन्दोलन खड़ा हुआ, जो भारत की शान्ति के और अन्यायपूर्ण भूमि-समस्या के परिहार के उपाय के रूप में प्रकट हुआ । आगे चलकर यही भूमिदान-आन्दोलन के रूप में विस्तृत हुआ ।

इस प्रकार शान्ति-सेना के धाम के निम्न पहलू प्रमुख हैं .

१. संपर्क की बारणीभूत सकीर्ण मान्यताओं और दृष्टिकोणों का निवारण करना,

२ सामाजिक अन्याय दूर करना, जिससे आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो,

३ देशभर में शान्तिमय परिस्थिति बनाये रखने का आश्वासन देना,

४ हिंसक उपद्रवों का शमन करने के प्रयत्न में शान्तिमय साधनों से जूझना और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना शरीर छोड़ने की तैयारी रखना,

५ और इन सब उपायों के द्वारा भारत में अहिंसक समाज-रचना की नींव डालना, जो विश्वव्यापी सहयोग और कल्याण का मार्ग प्रगस्त करने-वाला हो और युद्ध को सदा के लिए समाप्त करे ।

शान्ति-सेना का कार्य

गांधीजी के कुछ साथियों ने जगह-जगह शान्ति-सेना के कुछ छोटे-छोटे संगठन बना तो लिये थे, लेकिन गांधीजी को अपनी कल्पना के अनुसार शान्ति-सेना के विचार को ठोस रूप देने का मौका नहीं मिला। विनोबाजी ने अगस्त १९५७ में केरल की पदयात्रा के बीच अखिल भारतीय स्तर पर शान्ति-सेना खड़ी करने का बीड़ा उठाया। उसी समय उन्होंने शान्ति-सैनिकों का एक छोटा मण्डल गठित भी किया।

इस समय भारतभर में कोई १२,२४२ शान्ति-सैनिक हैं।

१८ साल से बड़ी उम्र का जो भी व्यक्ति, जो निम्नलिखित घोषणा और प्रतिज्ञा करता है, शान्ति-सैनिक बन सकता है।

“मैं विश्वास करता हूँ कि

१ सत्य और अहिंसा पर आधारित नया समाज बनना चाहिए।

२ समाज में होनेवाले सारे संघर्ष अहिंसक साधनों से हल हो सकते हैं और होने चाहिए, खासकर इस अणु-युग में।

३ मानवमात्र में मूलभूत एकता है।

४ मुक्त मानवता के विकास में बाधक है और अहिंसक जीवन-मन्यति का विपर्यय है, इसलिए

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि

१ शान्ति के लिए काम करूँगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण समर्पण करने को तैयार रहूँगा।

२ जाति, सम्प्रदाय, रंग, पक्ष आदि भेदा से ऊपर उठने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये भेद मनुष्य की एकता को मानने से इनकार करते हैं।

- ३ किसी युद्ध में शरीक नहीं होऊँगा ।
- ४ सुरक्षा के अहिंसक साधनों तथा वातावरण को बनाने के लिए सहायता करूँगा ।
- ५ नियमित रूप से अपना कुछ समय अपने मानव-बन्धुओं की सेवा में लगाऊँगा ।
- ६ शान्ति-सेना के अनुशासन को मानूँगा ।”

प्रत्येक शान्ति सैनिक का नाम किसी शान्ति केन्द्र में दर्ज होगा और वह उससे जुड़ा रहेगा । एक वर्ष तक परीक्षण की स्थिति में रहेगा और उस अवधि में यदि वह स्वयं त्यागपत्र देकर नहीं हटा गया या चारित्र्य-सम्बन्धी शिकायत के कारण उसे केन्द्र ने हटा नहीं दिया, तो वह विधिवत् शान्ति-सैनिक माना जायगा ।

शान्ति-केन्द्र

एक गाँव या मुहल्ले में दो या अधिक शान्ति-सैनिक हैं, तो वे मिलकर शान्ति-केन्द्र बना सकते हैं । यह शान्ति-सेना की बुनियादी इकाई है ।

अपेक्षा यह है कि इन सैनिकों की बैठक कम-से-कम सप्ताह में एक बार हो, जिसमें पिछले सप्ताह के काम की जानकारी दी जाय और आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनायी जाय । इनके कार्यक्रम सामान्यतः ये हो सकते हैं समाज में कहीं कोई अशान्ति का लक्षण दिखाई दे, तो उसके परिहार का प्रयत्न करना, कोई-न-कोई समाज-सेवा, नियमित स्वाध्याय, खेल-कूद वगैरह ।

यद्यपि जगह-जगह की विशेष परिस्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कार्यक्रम भिन्न-भिन्न हो सकता है, फिर भी उनके तीन प्रमुख विभाग किये जा सकते हैं—धर्म, सेवा और स्वाध्याय ।

जिले में अधिक केन्द्र हो, तो उनके बीच सहयोग बनाये रखने के लिए जिला-स्तर वा एक संयोजक या शान्ति सेना समिति रहेगी । इस समिति

का गठन प्रादेशिक शान्ति-सेना समिति करेगी। प्रादेशिक शान्ति-सेना मण्डल अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल के अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर इस समिति का गठन करेगी। राज्य शान्ति-सेना समिति का काम राज्य में शान्ति-सेना के काम का आयोजन करना और जहाँ आवश्यकता पड़े, वहाँ शान्ति-सैनिकों को भेजना है।

अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल को सर्वे सेवा सच का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। यह मण्डल देशभर में शान्ति-सेना का विचार फैलाने और सभी समितियों का संयोजन करने का काम करेगा। मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा। इस समय श्री जयप्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष हैं। विनोबाजी शान्ति-सेना के प्रमुख सेनापति हैं, अर्थात् शान्ति सैनिकों को आदेश देने का अन्तिम अधिकार उनके हाथ में है। शान्ति-सेना के वैधानिक संगठन के किसी पद पर विनोबाजी नहीं हैं, लेकिन मण्डल के सभी महत्त्व के निर्णय उनकी सलाह से ही लिये जाते हैं।

अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या शान्ति-सेना सफल हो सकती है? गत नौ वर्षों के अनुभव से इसके प्रति श्रद्धा सुदृढ़ हुई है और इससे निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। आवश्यकता को देखते हुए आज वह सेना बहुत छोटी पड़ती है। विनोबाजी की वत्पना है कि ५ हजार लोगों के बीच एक शान्ति-सैनिक हो। इसका अर्थ यह कि पूरे भारत के लिए लगभग ९०,००० शान्ति-सैनिक आवश्यक होंगे। लेकिन आज केवल १२,००० ही हैं और उनमें भी आधे बिहार में हैं। फिर भी इस छोटी-सी शक्ति ने जो काम किया है, जो सफलता प्राप्त की है, वह कम सराहनीय नहीं है।

प्रदर्शनों और झगड़ों के मामले में कई बार शान्ति सैनिक हिसक उपद्रव को टालने में सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में पुष्प राज्य के लिए जब आन्दोलन चला था, तब शान्ति बनाये रखने में शान्ति-सैनिकों ने विशेष प्रयास किया था। उन्होंने जुलूस निकाले, नेताओं से मिले, कई परचे प्रकाशित किये। कई बार तो जनता और पुलिस के बीच घटे रह-कर संघर्ष को बचाया। पुलिस पर इनका इस वदर प्रभाव रहा कि पुलिस

को भीड़ पर साठों घण्टे में हाथ रोक लेता पड़ा। पुलिस ने द्वा मेवालों की सराटना की और जब ये अहमदाबाद गये जानेवाले थे, तब यहाँ रुकने के लिए प्रार्थना की।

इंदौर में मिल-मालिकों और मजदूरों के बीच हुए झगड़ों में कम-से-कम तीन बार हिमा-बाण्ड होने-दोने बसाया।

सन् १९६१ के उत्तर प्रदेश के मागप्रदायिक झगड़ों में आगरे के शान्ति-सैनिक गजग रहे और शहर में अशान्ति न होने देने में काफी सहयोग दिया। सन् १९६४ में बिहार और उड़ीसा में जब भयानक हत्याबाण्ड हुआ, तब उसकी आँख छहमपुर में भी पहुँची, लेकिन यहाँ के स्थानीय शान्ति-सैनिकों की मजबूतता के कारण कोई अवांछित या अनिष्ट घटना नहीं होने पायी।

यहाँ अन्य प्रसंगों में विवाद को सुलझाने में उपवास का सहारा लेना पड़ा और यह सफल रहा। बैरल में नावों के तिराये को लेकर विवाद पड़ा हुआ था, तब यहाँ के उच्च श्रेणी के नेता श्रीबेलप्पन् ने उसके शान्ति-पूर्ण समाधान के लिए उपवास किया था। तिराये में वृद्धि होने के कारण उसके विरोध में विद्यार्थी पड़े हो गये थे और भारी उपद्रव होनेवाला था। उड़ीसा में सरकार और विद्यार्थियों के बीच बड़ा विवाद पड़ा हुआ था, जो लगभग दो महीने तक चलता रहा। उसके शान्तिमय समाधान के लिए आचार्य हरिहर दास ने उपवास किया, जिससे विवाद शान्त हुआ। मद्रास में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के नियंत्रण के लिए विनोबाजी को उपवास करना पड़ा था, यह सब जानते हैं।

विशाल और हिंसक उपद्रवों में शान्ति-सैनिकों ने सामान्यतया जनता को समझाने और हिंसा को रोकने का प्रयास किया है। आम तौर पर घोड़े-से स्थानीय सैनिक जितना कर सकते थे, उतना उन्होंने किया। सूचना मिलते ही बड़ी सज्ज्या में बाहर से शान्ति-सैनिक फौरन् यहाँ चले आये। लोगों को शान्त करने में, सशय के वातावरण को मिटाने में और बेघर लोगों को फिर से बसाने में इन लोगों ने बड़ा सराहनीय काम किया। इन्हें अच्छी सफलता मिली। असम में जब बगला-विरोधी दंगे हुए, तब भी भारत

के कोने-कोने से शान्ति-सैनिक वहाँ गये थे । श्री जवाहरलालजी की माँग पर बाद में विनोबाजी भी असम पहुँचे और वहाँ के शान्ति-सैनिकों का मार्गदर्शन किया ।

सिंहभूम, राँची और सुन्दरगढ़ जिलों में जब साम्प्रदायिक दंगे हुए, तब बिहार और उड़ीसा के शान्ति सैनिक पीड़ित क्षेत्रों में बड़ी सख्या में गये । यहाँ भी उनका काम बड़ा सफल और प्रभावशाली रहा । दंगे में भाग लेनेवालों में कई लोगों को इन्होंने समझाया, जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने अपने दुष्कर्म के लिए पश्चात्ताप किया और जिनके घर जला दिये गये थे, उनके घर फिर से बाँधने में अपनी ओर से उन्होंने मदद तक की ।

सीतामढ़ी (बिहार) में अल्पसंख्यक जाति के लोगों के घर जल जाने के प्रश्न को लेकर साम्प्रदायिक हिंसा फूटी थी । लेकिन उसे आगे बढ़ने से रोकने में शान्ति सैनिक सफल रहे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक दंगों में, मद्रास के हिन्दी-विरोधी उपद्रवों में तथा पंजाब के पंजाबी विरोधी दंगों में भी शान्ति-सैनिकों ने शान्ति-स्थापना का काम किया ।

अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उपद्रवों में बाहर के शान्ति-सैनिक समय पर पहुँच नहीं पाते हैं और उपद्रव को रोक नहीं पाते हैं, बल्कि स्थानीय शान्ति-सैनिक पर्याप्त सख्या में हों, तो उपद्रवों को न होने देने में वे सफल हो सकते हैं । यह तो स्पष्ट है कि विनोबाजी की कल्पना के अनुसार ५,००० लोगों के बीच कम-से-कम एक शान्ति सैनिक भी ठीक से काम करने लगे तो शान्ति बनाये रखने का वह एक अच्छा बल साबित हो सकता है ।

शान्ति-सेना का एक और महत्वपूर्ण काम यह रहा है कि दीन-दलित लोगों को विविध दबाव और शोषण से बचाने में काफी योगदान दिया गया है । पूर्णिया (बिहार) और कोरापुट (उत्तर) क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और रिश्ततखोरी को खत्म करने में वे सफल हुए हैं । कोरापुट के दीन-हीन आदिवासियों में निर्भयता निर्माण करने में भी बड़ी सफलता मिली है ।

पूना में खडकबागला बाँध के टूटने से बाढ़ आने पर, आन्ध्र में सूफान

के कारण तथा बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके के उन प्राकृतिक सफ़टों के बीच भी शान्ति-सेना ने काफी परिश्रमपूर्वक काम किया है ।

शान्ति-सेवा दल

यह शान्ति-सेना की एक शाखा है । इसके लिए एक साधारण सकल्प लेना होता है । कोई भी स्वच्छा से यह सकल्प लेकर इस दल का सदस्य बन सकता है । इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है, जो शान्ति-सैनिक की प्रतिज्ञा तो लेने में असमर्थ होंगे, लेकिन शान्ति चाहते हैं और शान्ति-स्थापना के लिए कुछ-न-कुछ करना चाहते हैं ।

इसके दो भाग हैं । एक है किशोर-शान्तिदल, जिसमें १२ से १८ वर्ष तक के किशोर शामिल हो सकते हैं । और दूसरा तरुण-शान्तिदल है, जिसमें १८ से ३० वर्ष तक के युवक भाग ले सकते हैं । इस देश में इन दिनों कम ही उपद्रव ऐसे होते हैं, जिनमें किशोरों का हाथ न रहता हो । किशोर-शान्तिदल चाहता है कि किशोरों और युवकों के विधायक सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हो और उनकी शक्ति को सृजनात्मक तथा लाभदायी प्रवृत्तियों की ओर मोड़ा जा सके ।

सन् १९६४ से प्रतिवर्ष किशोर-शान्तिदल के वार्षिक शिविर आयोजित हो रहे हैं । ये शिविर काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इन शिविरों में भाग लेनेवाले कई युवक तथा युवतियाँ अपने-अपने क्षेत्र में दल की शाखाएँ खोल रहे हैं और उपयोगी कार्यक्रम चला रहे हैं ।

तरुण-शान्तिदल का यह प्रयत्न है कि देश में संगठित और समर्थ एक सेवा-शक्ति खड़ी की जाय, जो रचनात्मक प्रवृत्तियों और समाज-सेवा के काम में लगे । इन दोनों शाखाओं के द्वारा शान्ति-सेना देहात और शहर, दोनों क्षेत्रों में काम कर रही है । शहरों में तो शान्ति-सेना ही एकमात्र अत्यन्त प्रमुख सर्वोदयी कार्यक्रम है । अधिकतर समय, तनाव, दंगे शुरू में शहरों में ही फूट पड़ते हैं । इसलिए जड़ में ही इनको रोकने का काम काफी महत्व का है ।

देहातो के लिए त्रिविध कार्यक्रम के एक अंग के तौर पर शान्ति-सेना का महत्त्व अत्यधिक है। जहाँ ग्रामदान देश को खोखला बना देनेवाले आकस्मिक सघर्षों की जड़ को निर्मूल करने का प्रयत्न करता है, वहाँ जनता में ग्रामदान के तत्त्व और विचार को फैलाने का महत्त्वपूर्ण काम शान्ति-सेना को करना है। जो गाँव ग्रामदान में आ जाता है, वहाँ जो-जो काम करते हैं, उगमें भी एक बहुत प्रमुख काम यह है।

ग्रामदानी गाँवों में भी तनाव और सघर्ष होंगे ही। गाँव गाँव के बीच भी सघर्ष हो सकते हैं। मुकदमेबाजी देहातो के लिए एक घातक अभिशाप है। उनका भाग्य इसी पर लटकता रहता है। इसके कारण शान्ति भंग होती है। कई समाज विरोधी व्यवहार और अपराध-समस्याओं का भी देहातो को सामना करना पड़ता है। देहाती क्षेत्र के शान्ति-सैनिकों और सेवकों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है।

गणवेश

शान्ति-सैनिक जब कार्यरत होते हैं, तब अपेक्षा यह है कि वे सफेद वस्त्र पहने रहें और सिर पर खादी का पीला रुमाल बाँधें। रुमाल २४ इंच चौड़ा, २४ इंच लम्बा होना चाहिए, उसे त्रिकोणाकार में मोड़कर सिर पर लपेट लेना चाहिए।

शान्ति-सेवकों को भी सफेद कुर्ता या कमीज पहनना चाहिए और शान्ति-सैनिकों की ही तरह का खादी का पीला रुमाल अपने गले में, स्काउट की तरह बाँधना चाहिए, सिर पर नहीं। साथ ही कमर पर खादी का पीला पट्टा भी बाँधना होगा। सीने की बायी ओर लगाने के लिए इनको एक बैज भी दिया जाता है।

सर्वोदय-पात्र

सर्वोदय-पात्र शान्ति-सेना के कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग है। जो भी गृहस्थ इस कार्यक्रम का समर्थन करता है, उससे अपेक्षा यह है कि घर में एक पात्र निश्चित स्थान में रखे, और उसमें रोज एक मुट्ठी अनाज डाले।

यह शान्ति-सेना के काम के लिए उनकी सम्मति तथा सहायता के लिए है। विनोबाजी चाहते हैं कि यह अनाज घर के सबसे छोटे बच्चे की मुट्ठी से डलवाया जाय। इससे बच्चों में ठेठ बचपन से ही दूसरों के लिए देने की भावना अर्थात् समाज भावना निर्माण होने में मदद मिलती है।

इस समय आंध्र और मद्रास के प्रमुख शहरों में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से सर्वोदय-यात्रा का सगठन और संचालन हो रहा है।

अन्य कार्यक्रम

सन् १९६२ में हिन्दू-चीन-संधर्ष के दिना में सर्व सेवा सघ ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था। उसमें कहा गया है

“सीमावर्ती जनता में अहिंसक प्रतीकार की शक्ति बढ़ाना हमारा एक प्रमुख काम है। शान्ति-सैनिकों को चाहिए कि जहाँ-जहाँ सम्भव हो, वहाँ सब जगह लोगों को वे स्वायत्तशील बनायें और आम्रमण का सामना असहयोग के द्वारा करने की प्रेरणा दें। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर शान्ति-सैनिकों को अपने प्राण छोड़ने को तैयार होना चाहिए और इस प्रकार दूसरा को भी बँसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए।”

देश की भावात्मक एकरा को सुदृढ़ करने तथा अहिंसक प्रतीकार की भावना जाग्रत करने के इस दोहरे काम में सहयोग देने के लिए सर्व सेवा सघ ने अहिंसा में विद्वान् करनेवाले अन्याय व्यक्तियों और सत्याग्रहियों को भी आमन्त्रित किया।

इस आमन्त्रण के पत्रस्वरूप इसी उद्देश्य के लिए देश की सभी प्रमुख सत्याग्रहों का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक समन्वय-समिति का गठन किया गया। इस समिति के निर्देशन में सीमा-क्षेत्रों के अन्दर कोई १२६ केन्द्र बांँत कर रहे हैं। ये निम्न प्रकार हैं

असम में ३८, उत्तराखण्ड में ३४, पूँजिया में ३९, नेपा में ७, बंगाल में ३, उत्तर पंजाब में २, तामाङ्ग में २ और हिमाचल प्रदेश में १। बाद में तय किया गया कि पाकिस्तान की ओर को भारत की सीमा में भी इस प्रकार का काम चालू किया जाय। शान्ति-सेना इन कार्यों में लगी है।

सीमा-क्षेत्र के काम का प्रमुख उद्देश्य यह है

- १ सीमावर्ती जनता में भारत के दूसरे भागों के साथ एकात्मता का विकास करना,
- २ सीमा-क्षेत्र के लोगों की सैनिक तथा भौतिक प्रगति में सहायता देना,
- ३ आक्रमण का अहिंसक प्रतीकार करने की भावना निर्माण करना और
- ४ मैत्री की भावना निर्माण करना, जो सीमा के बाहरी इलाकों में भी प्रभाव डाल सके ।

इन केन्द्रों में जो कुछ काम अब तक चला है, उससे काफी उत्साह मिलता है । यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि नेफा में जो केन्द्र खोले गये हैं, वे स्व० जवाहरलाल नेहरू के सुझाव के आधार पर खोले गये और उस क्षेत्र में सेवा के लिए खोले गये सबसे पहले के केन्द्र ये ही हैं । उससे पहले तब यह नीति मानी गयी थी कि उन क्षेत्रों को भारत के दूसरे भागों से अछूता रखा जाय ।

दिल्ली-पेकिंग मैत्री-यात्रा

भारत और चीन के बीच मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से सन् १९६३ के मार्च में यह यात्रा हुई थी । भारतीय शान्ति सेना की ओर से 'वर्ल्ड पीस ग्रीन्ड' से प्रार्थना की गयी थी कि वह इस यात्रा का सयोजन करे और सन्तुष्ट होकर इसका आयोजन हुआ था ।

यह सही है कि यात्रा का हेतु सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि चीन-सरकार ने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी । लेकिन भारत-सरकार ने अपने देश में एक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री-टोली को इस हेतु से यात्रा करने की अनुमति देकर अपनी उदारता दर्शायी । इस यात्रा के कारण देश में सुद-मानस को कुछ हद तक शीतल करने में सहायता मिली ।

नागालैण्ड-शान्ति मिशन

नागालैण्ड-शान्ति मिशन में श्री जयप्रकाश नारायण के होते हुए भी, उसमें शान्ति-सेना मण्डल का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। फिर भी शान्ति-सेना मण्डल वहाँ की समस्या के समाधान में काफी रुचि लेता रहा और उसने कोहिमा में अपना एक केन्द्र भी खोला है।

शान्ति-सेना मण्डल मानता है कि नागा-प्रदेश भारत का अंग है, लेकिन मण्डल यह भी महसूस करता है कि इन विद्रोह के दिनों में नागा लोगो पर जो अत्याचार हुआ है, उसके कारण उन लोगो के मन में अत्यधिक कटुता पैदा हुई है। शान्ति मिशन के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई वर्षों के बाद पहली बार वहाँ शान्ति स्थापित हो पायी। वहाँ के लोगो के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ और इससे शान्तिपूर्ण समाधान का मार्ग खुल गया।

उपसंहार

पिछले अध्यायो में ग्रामदान, खादी और शान्ति-सेना, इन तीनों कार्यक्रमों के विविध पहलुओं की चर्चा की गयी । लेकिन जैसे विनोबाजी कहते हैं, ये तीनों कार्यक्रम जबरदस्ती जोड़े गये तीन भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि एक ही मूर्ति के तीन मुँह के समान एक ही कार्यक्रम के तीन अंग हैं । उस मूर्ति की उपासना एक ही मूर्ति के रूप में करनी है, अलग-अलग मुँह की अलग-अलग उपासना नहीं ।

आज भारत, बल्कि सारा विश्व ही तीन प्रकार के रोगों से पीड़ित है । वे रोग हैं पूँजीवाद, नौकरशाही और सैनिकवाद । विविध कार्यक्रम के ये तीनों अंग उन तीनों रोगों के उपचार के प्रतीक हैं । ग्रामदान से विवेक-वृद्ध अर्थ-रचना और प्रशासन की नींव पड़ती है । और इस प्रकार नौकर-शाही का इलाज प्रस्तुत होता है, खादी और ग्रामोद्योगों से पूँजीवाद समाप्त हो सकता है तथा शान्ति-सेना से पुलिस और सेना की आवश्यकता खत्म हो जाती है ।

वे तीनों रोग यद्यपि भिन्न-भिन्न रोग दिखाई देते हैं, तथापि वस्तु-स्थिति यह है कि वे तीनों एक ही मूल रोग के तीन प्रकट लक्षण हैं । उसी प्रकार तीनों उपचार भी एक ही कारणर साधन के तीन पथ्य के रूप में हैं ।

लेकिन यह समय ग्रामदान-तूफान अभियान का है । बड़ी सख्या में ग्रामदान प्राप्त करने के लिए हजारों कार्यकर्ता प्रयत्नशील हैं । बाकी दोनों अंगों की उपेक्षा हो रही है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है ।

विनोबाजी के ही शब्दों में कहना है, तो ग्रामदान एक ऐसी युनियाद है, जिसके आधार पर खादी और शान्ति-सेना का निर्माण-आयं किया जा

सकेगा और तब ग्राम-स्वराज्य का भवन खड़ा हो सकेगा । बुनियाद डालने का काम पहले होना चाहिए । इसलिए ग्रामदान पर जोर देने का यह अर्थ नहीं है कि बाकी दो की उपेक्षा की जाती है ।

खादी-ग्रामोद्योगों का आयोजन और शान्ति-सेना का संगठन न करे, तो ग्रामदान का मूल हेतु सिद्ध ही नहीं होगा ।

दूसरी ओर अनुभव यह आ रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग वास्तव में तब तक प्रगति नहीं कर पाते हैं, जब तक गाँव-समाज खुद अपने हाथ में उन्हें न ले ले । आज देश के लगभग एक लाख गाँवों में खादी या ग्रामोद्योग का कुछ-न-कुछ काम चलता है । लेकिन ऐसे गाँव बहुत नहीं हैं, जहाँ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में इनका प्रमुख स्थान रहा हो । केवल ग्रामदान की भावना इन प्रवृत्तियों को उनकी लक्ष्य-सिद्धि की ओर ले जा सकती है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिन-जिन गाँवों में खादी-ग्रामोद्योग का कुछ काम चल रहा हो, उन गाँवों को ग्रामदान में शामिल करने का प्रयत्न किया जाय ।

देश की ज्वलन्त समस्या का हल करने का प्रयत्न ग्रामदान से हो रहा है । इसलिए ग्रामदान का सन्देश फैलाने में लगे हुए हजारों कार्यकर्ता और ग्रामवासी धस्तुतः शान्ति-सैनिक का ही काम कर रहे हैं, भले ही शान्ति-सैनिक के रूप में उन्होंने अपना नाम दर्ज न कराया हो । एक बार एक गाँव या क्षेत्र ग्रामदान हो जाता है तो फिर वहाँ शान्ति-सेना संगठित करना आसान हो जाता है, उसके लिए जनता की भारी सहमति मिल जाती है ।

तब पर भी देश में जो एवना का अभाव है, साम्प्रदायिकता है, संकीर्ण मनोवृत्ति है और स्वार्थपरता है, इन सबके कारण ग्रामदान के खिलाफ बड़ा विरोध और गतिरोध पैदा हो सकता है । उनका मुकाबला और ग्रामदान-भावना का बचाव करने का निरन्तर प्रयास करते रहना होगा । शान्ति-सेना और शान्ति-सेवा दृष्टि-ऐसी एक अद्वितीय शक्ति होगी, जो प्रति-क्रियाओं से ग्रामदान को बचाती रहेगी और आदर्शों की ज्योति को प्रज्वलित रखेगी ।

इस प्रकार आन्दोलन के ये तीनों अंग एक-दूसरे में ओतप्रोत हैं और अविभाज्य हैं। ये अपने में बाकी सभी रचनात्मक प्रवृत्तियों का आधार बनानेवाले हैं। श्री जयप्रकाशजी के शब्दों में उपमा देनी हो, तो ग्राम-स्वराज्य की तुलना बैलगाड़ी से की जा सकती है। ग्रामदान बैलों के समान गाड़ी की चालक शक्ति का काम करता है। छान्ति-सेना और खादी, दो पहिये के समान हैं। बाकी सब रचनात्मक कार्य गाड़ी में भरने का सामान है।

बैल न हो, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। ग्राम स्वराज्य की भी यही बात है। इसीलिए विनोबाजी ग्रामदान के रूप में चालक शक्ति निर्माण करने पर जोर देते हैं।

देश की आज की आर्थिक परिस्थिति और आंतरिक संघर्ष के कारण बड़ी विपत्ति आनेवाली है। विनोबाजी बराबर चेतावनी दे रहे हैं कि एक-मात्र ग्रामदान से ही देश खूनी क्रान्ति से बच सकेगा। इसकी तीव्रता की उत्कट अनुभूति से वे आज प्रेरित हो रहे हैं और हृदय से देश का तथा विश्व का कल्याण चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उस तीव्रता का अनुभव होना चाहिए।



परिशिष्ट : १

भूदान-प्राप्ति तथा वितरण के प्रान्तवार आँकड़े (मार्च १९६६ तक)

प्रान्त	जिलों की संख्या	भूमि प्राप्ति (एकड़ में)	भूमि वितरण (एकड़ में)	वितरण के अयोग्य सार्वज भूमि (एकड़ में)	वितरण के योग्य शेष भूमि (एकड़ में)
असम	१९	११,९३५	२६५		११,६७०
आंध्र	२०	२,४२,९५२	१,०३,३०८	८६,३८५	५३,२५९
उड़ीसा	१३	१,७३,८७२	१,०३,४१६	१५,२२२	५५,२३४
उत्तर प्रदेश	५४	४,३४,३५१	१,८४,२७४	१,३७,१२७	१,१२,९५०
बैराल	९	२६,२९३	५,७७४	७,९९९	१२,५२०
तामिलनाडु	१३	८०,४३३	२१,५१९	—	५८,९१४
दिल्ली	१	३००	१८०	१२०	—
पंजाब	१८	१४,७३९	३,६०१	३,३८०	७,७५८
गुजरात	१८	१,०३,२४२	५२,०८०	२७,९९४	२३,१६८
महाराष्ट्र	२५	१,५०,८०२	१,०७,१११	३८,३४३	५,३४५
मध्यप्रदेश	४३	४,०५,४०२	१,५६,५०६	१,७४,५३१	७४,३६५
मैसूर	१९	२०,०८६	३,१८१	५३	१६,८५२
बंगाल	१७	१२,९१८	३,८५६	८,४२६	६३६
बिहार	१७	२१,३२,७८७	३,११,०३७	१०,७९,७०१	७,४२,०४९
राजस्थान	२६	४,२९,४२८	९२,७३४	१,११,७५७	२,२४,९३७
हिमाचल	६	५,२४०	२,५३१	—	२,७०९
जम्मू-काश्मीर	१५	३११	५	—	२०६
	३३३	४२,४४,९९१	११,५१,३७८	१६,९१,०४१	१४,०२,५७२

भारत में ग्रान्तवार ग्रामदान (३० सितम्बर १९६६ तक)

ग्रान्त	तृफान के पहले के ग्रामदान मई '६५ तक	तृफान के बाद बलिया सम्मे- लन, अप्रैल '६६	कुल ग्रामदान ३० सितम्बर '६६ तक
१. बिहार	३५०	५,४६२	१०,७८३
२. उड़ीसा	२,४६९	२,२५१	५,२०५
३. मद्रास	३२५	६३८	१,८६७
४. मध्यप्रदेश	१८४	८७८	१,६२८
५. महाराष्ट्र	९१५	७५५	२,०५७
६. राजस्थान	३७८	४५६	९७०
७. गुजरात	२००	११४	४१६
८. आन्ध्र	५९५	४९०	२,१५२
९. प० बंगाल	३५४	२२८	५४२
१०. असम	९५७	—	१,२८६
११. पंजाब	६	—	४९१
१२. उत्तर प्रदेश	१२३	१८४	३६३
१३. हिमाचल प्रदेश	४	१३	१७
१४. केरल	४०३	६	४०९
१५. मैसूर	५८	—	५८
	७,३२१	११,६०९	२८,२४४

भारत में प्रखण्ड-दान (२५ अक्टूबर '६६ तक)

प्रान्त कुल	जिला	प्रखण्ड-दान
बिहार २३	हजारीबाग	१. प्रतापपुर
	पूर्णिमा	२. पूर्णिमा—सदर पूर्व
	दरभंगा	
	३. सरायरजन	४. बारिसनगर ५. उजियारपुर
	६. समस्तीपुर	७. ताजपुर ८. झंझारपुर
	९. कल्याणपुर	
	भागलपुर	
	१०. बिहपुर ११. गोपालपुर १२. नवगछिया	
	मुंगेर	
	१३. गोगरी १४. साहेबपुर कमाल १५. बलिया	
	पलामू	
	१६. गारु १७. मनिका	
	मुजफ्फरपुर १८. मुरौल	
	सारन १९. मौझी	
	सहर्षा २०. निर्मली	
	समाल परगना २१. सुन्दर पहाड़ी	
	शाहाबाद २२. अघौरा	
मद्रास १३	तिरुनेलवेली	
	२३. राघापुरम् २४. नायुनेरी २५. वल्लियूर	
	२६. कलक्कड २७. करन्गुलम् २८. पलायनकोट्टई	
	२९. विलयकुलम् ३०. कयायर	
	मदुराई	
महाराष्ट्र ७	३१. नत्तम् ३२. उत्तर मेलूर ३३. दक्षिण मेलूर	
	३४. अतनारपट्टी ३५. वडमदुराई	
	ठाणा	
	३६. कोसा ३७. सैवान ३८. तलासरी ३९. मोखाडा	
	४०. जवाहर विकासगढ ४१. मनोर	

	चादा	४२. सिरौचा
मध्यप्रदेश ४	५० निमाड	
	४३. निवाली ४४. सेंघवा	
	सिवनी	४५. कुरोई
	टीकमगढ	४६. टीकमगढ
उड़ीसा १३	कोरापुट	
	४७. नारायणपटना ४८. बन्धुगाँव ४९. दशमन्तपुर	
	५०. लक्ष्मीपुर ५१. रायगडा ५२. उमरकोट	
	५३. दाबूगाँव ५४. शरिगा	
	मयूरभञ्ज	
	५५. रासगोविन्दपुर ५६. मोरोडा ५७. बागरी	
	पोसी (प्र०) ५८. बागरी पोसी (द्वि०)	
	छेंकानाल	५९. कनकादहद
पंजाब ३	रोहतक	
	६०. मुडलाना ६१. कथूर	
	कागडा	६२. प्रागपुर
औध २	महबूबनगर	
	६३. अचमपेट ६४. कलुआकुर्ती	
गुजरात १	बडोदा	
	६५. बोरियाद	

भारत में तालुका-दान (२५ अक्टूबर १९६६ तक)

प्रान्त	जिला	तालुका
मद्रास	मदुराई	१. मेलूर
	तिरुनेलवेली	२. नागुनेरी
महाराष्ट्र	ठाणा	१. तलासरी
		२. मोखाडा

शान्ति-सेना समितियों के संयोजक

१ असम	श्री तरुण बरुआ, गोहाटी
२ बंगाल	श्री कृष्णकान्त चक्रवर्ती, बलकृष्ण १२
३ बम्बई	श्री लालू शाह, गाँवदेवी, बम्बई ७
४ गुजरात	श्री जगदीश लखिया, वडीदा-१
५ केरल	श्री के० दामोदरन्, त्रिचूर
६ महाराष्ट्र	श्री मोतीलाल भगो, बीड
७ मध्यप्रदेश	श्री चतुर्भुज पाठक, छतरपुर
८ पंजाब	श्री दादा गनेशीलाल, रेवाड़ी (गुडगाँव)
९ उत्तर प्रदेश	श्री विनय अवस्थी, कानपुर
१० राजस्थान	श्री वडीप्रसाद स्वामी, जयपुर
११ उत्कल	श्री रतनदास, राउरकेला (वडीसा)

परिशिष्ट : ५

भारत में शान्ति-सैनिक और शान्ति-केन्द्र (अगस्त '६६ तक)

क्रम	प्रान्त	शान्ति-सैनिक	शान्ति-केन्द्र
१.	बिहार	४,४७३	३४६
२.	उत्तर प्रदेश	२,६४१	१०५
३.	महाराष्ट्र	१,८७१	३००
४	राजस्थान	६९९	८४
५	मध्यप्रदेश	६१३	४१
६.	पंजाब	४०२	७
७	असम	३८०	८०
८.	बंगाल	२५२	१४
९.	उत्कल	२१५	३६
१०.	दिल्ली	१९५	—
११.	आंध्र	१७२	१
१२	गुजरात	१००	८
१३	केरल	६६	१९
१४	तमिलनाडु	५९	४५
१५	मैसूर	१७०	१२
१६	हिमाचल प्रदेश	७०	१२
१७	नागालैण्ड	—	२
१८.	नेपा	—	६
		१२,१६७	१,११८

● ये आँकड़े अधूरे हैं ।